

---

# **GAZETTE NOTIFICATION**

---

**16-7-2009 to 3-6-2011**

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 413-414

Dated 18-7-2009

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2009.

सा.का.नि. 105.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 56 की उप-धारा 2 के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण, इंजीनियर सदस्य भर्ती नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण, इंजीनियर सदस्य भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 के स्थान पर नया नियम रखा जाएगा.—दिल्ली विकास प्राधिकरण, इंजीनियर सदस्य भर्ती नियम, 2006 (जिसे इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्,

"2. नियुक्ति—दिल्ली विकास प्राधिकरण में इंजीनियर सदस्य के पद को नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी"

3. अनुसूची का संशोधन—उक्त नियमों की अनुसूची के स्तंभ (13) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

खोज-सह-चयन समिति का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा :—

- |   |          |
|---|----------|
| 1. सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय                        | —अध्यक्ष |
| 2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार          | —सदस्य   |
| 3. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण                            | —सदस्य   |
| 4. महानिदेशक (निर्माण), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग             | —सदस्य   |
| 5. भारत सरकार के अपर सचिव के समकक्ष स्तर का एक ज्येष्ठ इंजीनियर | —सदस्य"  |

[फा. सं. के-11011/18/2005-डीडीआईए]

सुजाता चतुर्वेदी, निदेशक (दिल्ली डिवीजन)

पाद टिप्पणी :—मूल नियम 5 जुलाई, 2006 के जीएसआर नं. 161 के तहत 8 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2009

G.S.R. 105.—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of Section 56 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Delhi Development Authority, Engineer Member Recruitment Rules, 2006, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Development Authority, Engineer Member Recruitment (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Substitution of new rule for rule 2.—In the Delhi Development Authority, Engineer Member Recruitment Rules, 2006 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely,

"2. Appointment.—The appointment to the post of Engineer Member, Delhi Development Authority, shall be made by the Central Government."

## MODIFICATIONS:

- (i) On page 4 of the said notification the word 'Bye-Laws' is replaced by the word 'Regulation', and the modified title shall read as under :

"Regulation for Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre"

- (ii) On page 5 of the said notification in para 05(g)—in 4, the word 'centre' shall be read as 'Centre'

- (iii) In the end of para 5(g) of the said notification, following is to be added :

"For such projects any reference to/clearance from DDA Technical Committee will no longer be required."

As such after modification the para 5(g) will read as under :

"All transportation projects/transportation Engineering solutions in Delhi by any agency having road Engineering/Infrastructure implication would require clearance of the Centre. This would ensure that latest technology and research finding support is available to all new roads and projects. For such projects any reference to/clearance from DDA Technical Committee will no longer be required."

- (iv) On page 6 of the said notification para 20 i.e. 'Repeal and Saving' is deleted.

[F. No. F. 5(44)2007/MP]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

3. **Amendment of Schedule.**—In the Schedule to the said rules, in column (13), for the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

“Search-cum-Selection Committee consisting of :—

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Secretary to the Government of India, Ministry of Urban Development                            | —Chairperson |
| 2. Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi                             | —Member      |
| 3. Vice-Chairman, Delhi Development Authority   | —Member      |
| 4. Director General (Works), Central Public Works Department                                      | —Member      |
| 5. One Senior Engineer equivalent to the level of Additional Secretary to the Government of India | —Member”.    |

[F. No. K-11011/18/2005-DDIA]

SUIJATA CHATURVEDI, Director (Delhi Division)

Foot Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, dated 8th July, 2006, vide, number G.S.R. 161, dated the 5th July, 2006.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2009/भाद्रपद 29, 1931

No. 463]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2009/SRAVANA 29, 1931

राष्ट्रीय विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 590(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 22 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ परामर्श करने के पश्चात् दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) संशोधन नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.—दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) नियम, 1981 के नियम 4 के उप-नियम (2) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस उप-नियम की कोई बात केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय निकाय, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन स्वशासी निकाय या संगठनों के संबंध में भूमि के आबंटन को प्रभावित नहीं करेगी"।

[फा. सं. के-11011/1/2009-डीडीआईए]

सुजाता चतुर्वेदी, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 872, तारीख 26 सितम्बर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक (1) सा.का.नि. 97, तारीख 27 जनवरी, 1989, (2) सा.का.नि. 677(अ), तारीख 11 नवम्बर, 1991, (3) सा.का.नि. 486(अ), तारीख 5 जुलाई, 2002, (4) सा.का.नि. 806(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2002, (5) सा.का.नि. 801(अ), तारीख 9 दिसम्बर, 2004 और (6) सा.का.नि. 220(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2006 द्वारा उनका पश्चात्पूर्ती संशोधन किया गया।

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT  
(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2009

G.S.R. 590(E).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (2) of Section 56, read with sub-section (3) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government, after consultation with the Delhi Development Authority, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Rule 4.**—In the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, in rule 4, in sub-rule (2), for the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that nothing contained in this sub-rule shall affect the allotment of land to the Central Government, State Government, Union Territory, local body, autonomous bodies or organizations owned by the Central Government".

[F.No.K-11011/1/2009-DDIA]

SUJATA CHATURVEDI, Director

Note: The principal rules were published *vide* number G.S.R. 872, dated the 26th September, 1981 and subsequently amended *vide* number (1) G.S.R. 97, dated the 27th January, 1989, (2) G.S.R. 677(E), dated the 11th November, 1991, (3) G.S.R. 486(E), dated the 5th July, 2002, (4) G.S.R. 806(E), dated the 3rd December, 2002, (5) G.S.R. 801(E) dated the 9th December, 2004 and (6) G.S.R. 220(E) dated the 19th April, 2006.

(2) सदस्य-सचिव संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का सेवारत अधिकारी होगा जो पर्यावरण विधियों से परिचित होगा।

(3) अन्य दो सदस्य या तो वृत्तिक या विशेषज्ञ होंगे जो इस अधिसूचना के दिशिष्ट VI में ही गई धारणाओं को पूरा करते हों।

(4) ऊपर उपरोक्त (3) में विनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक सदस्य जो पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया में विशेषज्ञ हो, एसईआईएए का अध्यक्ष होगा।

(5) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन उपरोक्त (3) से उपरोक्त (4) में विनिर्दिष्ट सदस्यों और अध्यक्ष के नामों को केन्द्रीय सरकार को अग्रप्रेषित करेगी और केन्द्रीय सरकार नामों के प्राप्ति को तारीख से तीस दिनों के भीतर उस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए एसईआईएए को एक प्राधिकरण के रूप में गठित करेगी।

(6) गैर पदावधि सदस्य और अध्यक्ष की (प्राधिकरण को केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से) तीन वर्षों की नियत पदावधि होगी।

(7) एसईआईएए के सभी विनिश्चय एकमत से होंगे और किसी बैठक में लिए जाएंगे।

#### 4. परियोजना और क्रियाकलापों का प्रवर्गीकरण :-

(i) सभी परियोजनाएँ या क्रियाकलाप मुख्यतः दो प्रवर्गों में प्रवर्गीकृत हों, प्रवर्ग 'क' और प्रवर्ग 'ख' संक्षम समाघात की स्थानिक सीमा और मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक तथा मानव निर्मित सतहों पर आधारित हैं।

(ii) अनुसूची में प्रवर्ग 'क' के रूप में सम्मिलित सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों, जिसके अंतर्गत विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार और आधुनिकीकरण तथा उत्पाद विधियों में परिवर्तन सम्मिलित है, के लिए, इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाने वाली किसी विशेषज्ञ आकलन समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अपेक्षित होगी।

(iii) अनुसूची में प्रवर्ग 'ख' के रूप में सम्मिलित सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों, जिसके अंतर्गत पैरा 2 के उपपैरा (ii) में यथाविनिर्दिष्ट विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार और आधुनिकीकरण या पैरा 2 के उपपैरा (iii) में यथाविनिर्दिष्ट ऊपर निर्धारण में परिवर्तन शामिल हैं, किन्तु जिसमें वे सम्मिलित नहीं हैं जो अनुसूची में विशेषज्ञ की गई साधारण शर्तों को पूरा करते हैं, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अपेक्षित होगी। एसईआईएए का अपना विनिश्चय, इस उस अधिसूचना में गठित की जाने वाली किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ आकलन समिति (एसईईए) का परामर्श पर आधारित होगा। एसईआईएए के रूप में गठित एसईआईएए का उद्देश्य, जो कि अनुसूचित हैं, कोई प्रवर्ग 'ख' परियोजना प्रवर्ग 'क' मानना या उसे प्रवर्ग 'क' में प्रवर्गित करना नहीं है।

5. स्कीनिंग, विस्तारण और आंकलन समिति :- केंद्रीय सरकार के स्तर पर वही विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य या संघ राज्य स्तर पर राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ईएसी और एसईएसी के रूप में संदर्भ प्रयोग किया जाएगा) परियोजनाओं या क्रियाकलापों की स्कीनिंग, विस्तारण और आंकलन करेगी। इसी और एसईएसी की एक साथ में कम से कम एक बार बैठक होगी।

(क) ईएसी का संरचना परिशिष्ट VI में दी जाएगी। राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर एसईएसी का कार्य संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से समान संरचना सहित गठन किया जाएगा।

(ख) केंद्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की पूर्व सहमति से प्रशासनिक सुविधा और लागत के कारणों से एक या अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक एसईएसी को गठन कर सकेगी।

(ग) विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी।

(घ) संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति के प्राधिकृत सदस्य उस परियोजना या क्रियाकलाप के संबंध में जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मांगी गई है, को स्कैन करने या विस्तार करने, या आंकलन के प्रयोजनों के लिए आवेदक को जो निरीक्षण के लिए आवश्यक होना चाहिए कम से कम सात दिन की पूर्व सूचना देगे।

(ङ) विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगा। अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सहमति बनाने का प्रयास करेगा और सहमति नहीं बन पाती है तो बहुमत का विचार माना जाएगा।

6. पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन (ईसी) :- सभी मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति मांगने के लिए कोई आवेदन परियोजना और/या क्रियाकलापों के लिए, जिससे आवेदन संबंधित है, आवेदक द्वारा स्थल पर किसी संनिर्माण क्रियाकलाप या भूमि का उपयोग के प्रारंभ के पूर्व, पूर्वक्षित स्थल (स्थलों) की पहचान के पश्चात् परिशिष्ट 2 में बतलाया है, यदि लागू हो, उससे संलग्न प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क में किया जाएगा। आवेदक, उसके सिवाय अन्य मांग परियोजनाओं या क्रियाकलापों (अनुसूची की गण 3) के मामले में प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क के अतिरिक्त पूर्व पर्यावरण परियोजना शिफ्ट की एक प्रति, पूर्व साक्ष्यता शिफ्ट के स्थान पर धारणा योजना की एक प्रति आदिम जल संचयन शिफ्ट।

7. (i) नई परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति (ईसी) प्रक्रिया के प्रक्रम :- नई परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति प्रक्रिया में सुविधात्मक तंत्र प्रक्रम समाविष्ट होंगे, जिनमें से सभी इस अधिसूचना में नीचे सूचीबद्ध विभिन्न मामलों में लागू नहीं होंगे। प्रक्रम प्रक्रम श्रृंखलाबद्ध क्रम में होंगे :-



- प्रक्रम (1) स्क्रीनिंग (केवल प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं और क्रियाकलापों के लिए)
- प्रक्रम (2) विस्तारण
- प्रक्रम (3) लोक परामर्श
- प्रक्रम (4) आंकलन

#### I. प्रक्रम (1) - स्क्रीनिंग :

प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में, यह प्रक्रम परियोजना की प्रकृति और अवस्थिति विनिर्देश पर आधारित पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने से पूर्व उसके आंकलन के लिए कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने के लिए यह अवधारण करने के लिए कि परियोजना या क्रियाकलाप के लिए आगे पर्यावरणीय अध्ययन करना अपेक्षित है या नहीं संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति (एसईएसी) द्वारा प्रक्रम 1 में पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मांगने के लिए किसी आवेदन की संवीक्षा होगी। कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की अपेक्षा करने वाली परियोजनाओं को प्रवर्ग "ख1" कहा जाएगा और शेष परियोजनाओं को प्रवर्ग "ख2" कहा जाएगा और उसके लिए कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट अपेक्षित नहीं होगी। मद 8ख के सिवाय परियोजनाओं के ख 1 या ख2 में प्रवर्गीकरण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर समुचित मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा।

#### II. प्रक्रम (2) विस्तारण :

(i) उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा प्रवर्ग 'क' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में विशेषज्ञ आंकलन समिति, और प्रवर्ग 'ख1' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में, राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति, जिसके अंतर्गत विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार और/या आधुनिकीकरण और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के विस्तार, सौंपे जाने वाले विस्तृत और व्यापक कार्य अवधारित करने के लिए, उस परियोजना या क्रियाकलाप के संबंध में कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने के लिए, सभी सुसंगत पर्यावरणीय समुत्थानों को, जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति ईप्सित की गई है, आवेदन सम्मिलित हैं। विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति विहित आवेदन प्ररूप 1/प्ररूप 1क में दी गई जानकारी के आधार पर सौंपे जाने वाले कार्य अवधारित करेगी, जिसके अंतर्गत आवेदक द्वारा सौंपे जाने वाले प्रस्थापित कार्य, किसी विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर आंकलन समिति के किसी सब ग्रुप द्वारा देखा गया कोई स्थल, यदि विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए, आवेदक द्वारा सुझाए गए सौंपे जाने वाले कार्य और अन्य सूचना जो विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति के पास उपलब्ध हो, सम्मिलित हैं। अनुसूची की मद 8 में प्रवर्ग ख के रूप में सूचीबद्ध सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों (संनिर्माण, नगरी/वाणिज्यिक काम्प्लेक्स/आवासन) के लिए विस्तार अपेक्षित नहीं होगा और उनका आंकलन प्ररूप 1/प्ररूप 1क और धारणा योजना के आधार पर किया जाएगा।

(ii) सौंपे गए कृत्यों को प्ररूप 1 की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा आवेदक को प्रेषित किया जाएगा। अनुसूची के प्रवर्ग क हाइड्रोक्लेक्ट्रिक परियोजना मद 1 (ग) (i) के मामले में सौंपे गए कृत्यों को पूर्व सनिमांश क्रियाकलापों के लिए अनापत्ति सहित प्रेषित किया जाएगा। यदि सौंपे गए कृत्यों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और प्ररूप 1 की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर आवेदक को प्रेषित किया जाता है तो आवेदक द्वारा सुझाए गए सौंपे जाने वाले कृत्य ईआईए अध्ययन के लिए अनुमोदित, अंतिम सौंपे गए कृत्यों के रूप में समझे जाएंगे। अनुमोदित सौंपे गए कृत्य, पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा संबंधित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

(iii) इसी प्रक्रम पर संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिश पर संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदनों को नामंजूर किया जा सकेगा। ऐसे नामंजूर किए जाने की दशा में, विनिश्चय को उसके कारणों सहित आवेदक को, आवेदन की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर लिखित में संसूचित किया जाएगा।

### III प्रक्रम (3) लोक परामर्श

(i) "लोक परामर्श" उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा स्थानीय प्रभावी व्यक्तियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों की चिंताओं को, जिनका परियोजना या क्रियाकलापों के पर्यावरणीय समाघातों में न्यायसंगत आधार है, समुचित रूप में अभिकल्पित परियोजना या क्रियाकलाप में संबंधित सभी सामग्री को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाएगा। सभी प्रवर्ग "क" और प्रवर्ग "ख" परियोजनाएं या क्रियाकलाप निम्नलिखित के सिवाय लोक परामर्श करेंगे :-

(क) सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण (अनुसूची की मद 1(ग) (ii))।

(ख) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित औद्योगिक संपदाओं या पार्कों के भीतर अवस्थित सभी परियोजनाएं या क्रियाकलाप (अनुसूची की मद 7(ग)) और जिन्हें ऐसे अनुमोदन में अनुज्ञात नहीं किया जाता है।

(ग) सड़कों और राजमार्गों का विस्तार (अनुसूची की मद 7(घ)) जिनमें भूमि का कोई और अर्जन अंतर्बलित नहीं है।

(घ) सभी भवन/संनिर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और नगरीय योजनाएं (मद 8)।

(ङ) सभी प्रवर्ग ख 2 परियोजनाएं और क्रियाकलाप।

(च) केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अवधारित राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी परियोजनाएं और क्रियाकलाप या जिसमें अन्य युद्धगत विचार अंतर्बलित हैं।

(ii) लोक परामर्श में साधारणतया दो घटक समाविष्ट होंगे :-

(क) स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों की चिंताओं को सुनिश्चित करने के लिए परिशिष्ट 4 में विहित शैली में की जाने वाली स्थल पर या उसके निकट परिसर में जिला वार कोई लोक सुनवाई।

(ख) परियोजना या क्रियाकलाप के पर्यावरणीय परभावों में कोई न्यायसंगत आधार रखने वाले अन्य संबंधित परभावों से निर्दिष्टा में प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना।

(iii) स्थल (स्थलों) पर या उसके निकट परिसर में सभी मामलों में लोक सुनवाई विनिर्दिष्ट रीति में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा की जाएगी और कार्यवाहियों को आवेदक से प्राप्त अनुरोध के पैंतालीस दिनों के भीतर संबंधित विनियामक प्राधिकरण को अग्रप्रेषित किया जाएगा।

(iv) यदि संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति लोक सुनवाई नहीं करती है और लोक सुनवाई को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी नहीं करती है और/या लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को विहित अवधि के भीतर यथाउपयुक्त संबंधित विनियामक प्राधिकरण को प्रेषित नहीं करती है तो विनियामक प्राधिकरण अन्य लोक अभिकरण या प्राधिकरण को, जो विनियामक प्राधिकरण का अधीनस्थ नहीं है, प्रक्रिया को पैंतालीस दिनों की और अवधि के भीतर पूरा करने के लिए लगाएगी।

(v) यदि ऊपर उपरोक्त (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट लोक अभिकरण या प्राधिकरण, संबंधित विनियामक प्राधिकरण को यह रिपोर्ट करता है, कि स्थानीय अवस्थिति के कारण लोक सुनवाई करना संभव नहीं है; तो किसी रीति में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किए जाने वाले संबंधित स्थानीय व्यक्तियों के विचारों का समर्थन करेंगे। वह उस तथ्य की रिपोर्ट संबंधित विनियामक प्राधिकरण को ब्यौरेवार देगा जो रिपोर्ट पर और अन्य विश्वसनीय सूचना पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात्, जिसका लोक परामर्श के लिए विनिश्चय किया गया है, उस दशा में जिसे लोक सुनवाई में सम्मिलित करने की आवश्यकता है, रिपोर्ट करेगा।

(vi) परियोजना या क्रियाकलापों के पर्यावरणीय पहलुओं में कोई न्यायसंगत आधार रखने वाले अन्य संबंधित व्यक्तियों से लिखित में प्रक्रिया अभिप्राप्त करने के लिए, संबंधित विनियामक प्राधिकरण और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, आवेदक द्वारा परिशिष्ट 3क में दिए गए प्ररूप में तैयार की गई संक्षिप्त ईआईए रिपोर्ट को उनके वेबसाइट पर देते हुए ऐसे संबंधित व्यक्तियों से लोक सुनवाई की व्यवस्था के लिए किसी लिखित अनुरोध की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर प्रतिक्रियाएं प्राप्त करेंगी। गोपनीय सूचना, जिसके अंतर्गत प्रकट न करने योग्य या विधिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त सूचना, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकार अंतर्भूत हैं, आवेदन में विनिर्दिष्ट स्रोत, वेबसाइट पर नहीं रखे जाएंगे। संबंधित विनियामक प्राधिकरण, परियोजना या क्रियाकलाप की बाबत विस्तृत प्रचार को सुनिश्चित करने के लिए अन्य समुचित मीडिया का उपयोग भी कर सकेगा। विनियामक प्राधिकरण, तथापि लोक सुनवाई की तारीख तक निरीक्षण के लिए प्रारूप ईआईए रिपोर्ट किसी संबंधित व्यक्ति से, सान्धान्य कार्यालय घंटों के दौरान अधिसूचित स्थान पर किसी लिखित अनुरोध पर उपलब्ध कराएगा। इस लोक परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में प्राप्त सभी प्रतिक्रियाएं शीघ्रतम उपलब्ध साधन से आवेदक को अग्रप्रेषित की जाएगी।

(vii) लोक परामर्श पूरा करने के पश्चात्, इस प्रक्रिया के दौरान अभिव्यक्त सभी सारवान पर्यावरणीय चिंताओं को संशोधित करेगा और प्रारूप ईआईए और ईएमपी में समुचित परिवर्तन करेगा। इस प्रकार तैयार की गई अंतिम ईआईए रिपोर्ट आवेदक के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी। आवेदक, लोक परामर्श के दौरान अभिव्यक्त की गई सभी चिंताओं को संबोधित करते हुए, प्रारूप ईआईए और ईएमपी की एक संक्षिप्त रिपोर्ट अनुकल्पतः प्रस्तुत करेगा।

#### IV प्रकम(4) - आंकलन :

(i) आंकलन से आवेदन और अन्य दस्तावेजों, ऐसे अंतिम ईआईए रिपोर्ट, लोक परामर्शों का निष्कर्ष, जिसके अंतर्गत लोक सुनवाई की कार्यवाहियां हैं, पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण को

आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा विस्तृत संवीक्षा अभिप्रेत है। यह आंकलन विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा किसी कार्यवाही को, जिसमें आवेदक को आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है, एक पारदर्शी रीति में किया जाएगा। इस कार्यवाही के निष्कर्ष पर विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति संबंधित विनियामक प्राधिकरण को निश्चित निबंधनों और शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने के लिए या पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन को नामंजूर करने के लिए उसके कारणों सहित स्पष्ट सिफारिशें करेंगी।

(ii) सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आंकलन जो लोक परामर्श के लिए अपेक्षित नहीं है या कोई पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, जैसा लागू हो विहित आवेदन प्ररूप 1 और प्ररूप 1क के आधार पर उपलब्ध सभी अन्य सुसंगत विद्यमान सूचना और दौरा किए स्थल को, जहां विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है, कार्यान्वित किया जाएगा।

(iii) किसी आवेदन का आंकलन, विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा अंतिम पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति या प्ररूप 1 या प्ररूप 1क के साठ दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा, जहां लोक परामर्श आवश्यक नहीं है, वहां विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों को सक्षम प्राधिकारों के समक्ष अगले पन्द्रह दिनों के भीतर अंतिम विनिश्चय के लिए रखा जाएगा। आंकलन की विहित प्रक्रिया परिशिष्ट V में दी गई है।

7. (ii) विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार या आधुनिकीकरण या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्रक्रिया-

उस क्षमता के परे जिसके लिए इस अधिसूचना के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर की गई है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि सहित या तो पट्टा क्षेत्र या खनन परियोजनाओं की दशा में उत्पादन क्षमता में वृद्धि सहित या इस अधिसूचना की अनुसूची में विहित अंतिम सीमा के परे कुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि सहित विद्यमान यूनिट के आधुनिकीकरण के लिए, प्रक्रिया और/या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के माध्यम से या उत्पाद मिश्रण में किसी परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति इच्छित करने वाले सभी आवेदन प्ररूप 1 में किए जाएंगे और उन पर संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा साठ दिनों के भीतर विचार किया जाएगा, जो सम्यक आवश्यक तत्परता से जिसके अंतर्गत ईआईए का तैयार किया जाना और लोक परामर्श भी है, विनिश्चय करेंगी और आवेदन का तदनुसार पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने के लिए आंकलन किया जाएगा।

8. पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर किया जाना या उसको खारिज किया जाना-

(i) विनियामक प्राधिकरण, संबंधित ई ए सी या एस ई ए सी की सिफारिशों पर विचार करेगा और अपने विनिश्चय को आवेदक को विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर प्रेषित करेगा या अन्य शब्दों में अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति के एक सौ पचास दिनों के भीतर प्रेषित करेगा और जहां पर्यावरणीय समाघात निर्धारण पूर्व आवेदन की प्राप्ति के एक सौ पचास दिनों के भीतर अपेक्षित नहीं है वहां अपेक्षित दस्तावेज, नीचे उपरोक्त के शिष्य प्रेषित करेगा।

## अनुसूची

(पैरा 2 और 7 देखें)

पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं या क्रियाकलापों की सूची

क्र. सं.	परियोजना या क्रियाकलाप	अवसीम सहित प्रयोग		शर्तें, यदि कोई हों
		क	ख	
1	खनन, प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्षण और विद्युत उत्पादन विनिर्दिष्ट उत्पादन क्षमता के लिए)			
1	2	3	4	5
1(क)	खनिज का खनन	खनन पट्टा क्षेत्र का $\geq 50$ हे० किसी भी खनन क्षेत्र का ध्यान दिए बिना ऐस्बेस्टज खनन	$< 50$ हेक्टेयर $\geq 5$ हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र	साधारण शर्तें लागू होंगी टिप्पण खनिज पदार्थों के पूर्वक्षण (जिसमें झिलिंग न हो) को छूट दी गई है बशर्त कि वास्तविक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों को पूर्व अनुमति ली गई है।
1(ख)	अपतट और तटवर्ती तेल तथा गैस की खोज, विकास और उत्पादन.	सभी परियोजनाएं		टिप्पण सार खोज सर्वेक्षण (जिसमें झिलिंग न हो) को छूट दी गई है बशर्त कि वास्तविक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों को पूर्व अनुमति ली गई है।
1(ग)	नदी घाटी परियोजनाएं	(i) $\geq 50$ मे०वा० जल विद्युत उत्पादन (ii) $\geq 10,000$ हे० खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	(i) $< 50 \geq 25$ मे०वा० जल विद्युत उत्पादन (ii) $< 10,000$ हे० खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	साधारण शर्तें लागू होंगी
1(घ)	तापीय विद्युत संयंत्र	(कोयला लिग्नाइट और नेपथा गैस आधारित) $\geq 500$ मे.वा. $\geq 50$ मे.वा. (पेटकोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन)	(कोयला/लिग्नाइट/नेपथा एवं गैस आधारित) $< 500$ मे.वा. (पेटकोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन) $< 50$ मे.वा $\geq 5$ मे.वा.	साधारण शर्तें लागू होंगी
1(ङ)	आणविक विद्युत परियोजनाएं और आणविक ईंधन का प्रसंस्करण	सभी परियोजनाएं		
2	प्राथमिक प्रसंस्करण			
2(क)	कोयला धोवनशालाएं	$\geq 1$ मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	$< 1$ मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	साधारण शर्तें लागू होंगी (यदि खनन क्षेत्र के अंदर स्थित है तो प्रस्ताव का मूल्यांकन खनन प्रस्ताव के साथ किया जाना चाहिए)

2(ख)	खनिज सज्जीकरण	$\geq 0.1$ मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	$< 0.1$ मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	साधारण शर्त लागू होगी अनापत्ति प्रदान करने के लिए खनन प्रस्ताव का खनिज सज्जीकरण के साथ ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए
पदार्थ उत्पादन				
3(क)	धातुकर्म उद्योग (सिरका और गैर फ़ैररी)	क) प्राथमिक धातुकर्म उद्योग सभी परियोजनाएं ख) स्पंज आयरन विनिर्माण $\geq 200$ टन पी डी ग) गौण धातु कर्म प्रसंस्करण उद्योग सभी विषाक्त और भारी धातु उत्पादित करने वाली इकाइयां $\geq 20,000$ टन/ वार्षिक	स्पंज आयरन विनिर्माण $< 200$ टन पी डी गौण धातु कर्म प्रसंस्करण उद्योग 1) सभी विषाक्त और भारी धातु उत्पादित करने वाली इकाइयां $< 20,000$ टन/ वार्षिक 2) अन्य सभी विषरहित गौण धातुकर्म प्रसंस्करण उद्योग $> 5000$ टन/ वार्षिक	स्पंज आयरन विनिर्माण के लिए साधारण शर्त लागू होगी
3(ख)	सीमेंट संयंत्र	वार्षिक उत्पादन क्षमता $\geq 1.0$ मिलियन टन	वार्षिक उत्पादन क्षमता $< 1.0$ मिलियन टन यह सभी ग्राइडिंग इकाइयों के लिए लागू है	साधारण शर्त लागू होगी
पदार्थ प्रसंस्करण				
4(क)	पेट्रोलियम रिफ़ाइनिंग उद्योग	सभी परियोजनाएं		
4(ख)	ग्रेक मट्टी संयंत्र	$\geq 2,50,000$ टन वार्षिक	$< 2,50,000$ एवं $\geq 25,000$ टन वार्षिक	
4(ग)	एस्बेस्टास मिलिंग और एस्बेस्टास आधारित उत्पाद	सभी परियोजनाएं		
4(घ)	क्लोस्कार उद्योग	उत्पादन क्षमता $\geq 300$ टन पी डी या अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा से बाध्य अवस्थित इकाई	उत्पादन क्षमता $< 300$ टन पी डी और अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में अवस्थित इकाई	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी किसी नए पार प्रकोष्ठ आधारित संयंत्र को अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और इस अधिसूचना द्वारा द्वितीय प्रकोष्ठ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करने वाली विद्यमान इकाई को छूट प्राप्त है।

4	सोडा भस्म उद्योग	सभी परियोजनाएं		
4(ब)	घनडा/त्वचा/खाल प्रसंस्करण उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र से बाहर सभी नई परियोजनाएं या औद्योगिक क्षेत्र के बाहर विद्यमान ईकाइयों का विस्तार	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में अवस्थित सभी नई परियोजनाएं या परियोजनाओं का विस्तार	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
उत्पादन/फीब्रिकेशन				
5	ससायनिक उर्वरक	सभी परियोजनाएं		
5(ख)	कीटनाशक उद्योग और कीटनाशक विशिष्ट मध्यक जीवभार (विनिर्मिति को छोड़कर)	तकनीकी श्रेणी के कीटनाशकों को उत्पादन करने वाली सभी ईकाइयां		
5(ग)	पेट्रो रसायन परिसर (पेट्रोलियम के अंश और प्राकृतिक गैस और/या सुगन्धितों में सुधार प्रसंस्करण आधारित उद्योग	सभी परियोजनाएं		
5(घ)	मानव निर्मित फाइबर का उत्पादन	रसन	अन्य	साधारण शर्त लागू होगी
5(ङ)	पेट्रो रसायन आधारित प्रसंस्करण ( भंजन से भिन्न अन्य प्रसंस्करण तथा सुधार और जो परिसर के भीतर समाविष्ट नहीं है )	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाह्य अवस्थित	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के भीतर अवस्थित	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
5(च)	संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन उद्योग (रंजक और रंजक मध्यक; थोक औषधि और औषधि विनिर्मितियों को छोड़कर मध्यक: संश्लिष्ट रबड़ मूल कार्बनिक रसायन, अन्य संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन और रसायन मध्यक)	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाह्य अवस्थित	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के भीतर अवस्थित	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
5(छ)	आसवनी	(i) सभी शीश आधारित आसवनी । (ii) सभी गन्ने का रस/गेर -शीश आधारित आसवनी $\geq 30$ कि०ली० दैनिक	सभी गन्ने का रस/गेर शीश आधारित आसवनी $< 30$ कि०ली० दैनिक	साधारण शर्त लागू होगी
5(ज)	समेकित पेंट उद्योग		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
5(झ)	अपशिष्ट कागज से कागज का निर्माण और तैयार लुग्दी और विरंजन किए बिना तैयार लुग्दी से कागज निर्माण के अलावा लुग्दी एवं कागज	लुग्दी विनिर्माण और लुग्दी और कागज विनिर्माण उद्योग	लुग्दी विनिर्माण के बिना कागज विनिर्माण उद्योग	साधारण शर्त लागू होगी

	उद्योग			
5(अ)	चीनी उद्योग		गन्ना पेरने की क्षमता $\geq$ 5000 टन दैनिक	साधारण शर्त लागू होगी
5(ट)	प्रेरण/आर्क मट्टी/कुपोला मट्टी 5 टन प्रति घंटा या ज्यादा		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
6	सेवा सेक्टर			
6(क)	राष्ट्रीय उद्यानों/ अमयारण्यों/ प्रवाल भित्तियों/ एल एन जी टर्मिनल सहित पारिस्थिकीय संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाली तेत और गैस परिवहन पाइप लाइनें (अपरिकृषा और परिष्करणी/पेट्रो रसायन उत्पाद)	सभी परियोजनाएं		
6(ख)	एकल मंडारकरण और परिसंकटमय रसायन को संभालना (एमएसआईएवसी नियम, 1989 और 2000 की संशोधित अनुसूची 2 और 3 के स्तंभ 3 में उपदर्शित अवसीमा योजना परिमाण के अनुसार		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
7	पर्यावरणीय सेवाओं सहित भौतिक अवसंरचना			
7(क)	विमानपत्तन	सभी परियोजनाएं		
7(ख)	सभी पोत भंजन यार्ड जिलमें पोत भंजन इकाई भी सम्मिलित है	सभी परियोजनाएं		
7(ग)	औद्योगिक सम्पदा/पार्क/परिसर/ क्षेत्र/निर्यात प्रसंस्करण जोन (नि.प्र.जो.), विशेष आर्थिक जोन (वि.आ.जो.) जैव प्रौद्योगिकी पार्क घमड़ा परिसर	प्रस्तावित औद्योगिक संपदा में यदि एक भी उद्योग श्रेणी क के अंतर्गत आता है तो पूरे औद्योगिक क्षेत्र को श्रेणी क ही समझा जाएगा चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो  500 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र की औद्योगिक संपदाएं और जिनमें कम से कम एक श्रेणी ख का उद्योग स्थित हो	औद्योगिक संपदाएं और जिनमें कम से कम एक श्रेणी ख का उद्योग स्थित है और क्षेत्र < 500 हेक्टेयर हो  औद्योगिक संपदाएं क्षेत्र > 500 हेक्टेयर और जिनमें श्रेणी क या ख श्रेणी का कोई उद्योग नहीं है	विशेष शर्त लागू होगी टिप्पण 500 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की औद्योगिक संपदाओं जिनमें क या ख श्रेणी का कोई उद्योग नहीं है, को मंजूरी की आवश्यकता नहीं है
7(घ)	सामान्य परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार मंडारकरण और निपटान सुविधाएं (उ.नं.नि.स.)	सभी एकीकृत सुविधाएं जिनमें भस्मीकरण और नृमिभरण या केवल भस्मीकरण शामिल है	केवल भूमि भरण वाली सभी सुविधाएं	साधारण शर्त लागू होगी



7(ड)	पत्तन, बंदरगाह	≥ 5 मिलियन टन वार्षिक स्थोरा की उठाई-धराई की क्षमता (मत्स्य बंदरगाह से भिन्न)	< 5 मिलियन टन वार्षिक स्थोरा की उठाई-धराई की क्षमता और पत्तन/बंदरगाह में ≥ 10,000 टन वार्षिक मछली पकड़ने की क्षमता	साधारण शर्त लागू होगी
7(च)	राजमार्ग	1) नए राष्ट्रीय राजमार्ग; और 2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है और एक से अधिक राज्यों से गुजरते हैं।	1) नए राज्य राजमार्ग; और 2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबे राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है।	साधारण शर्त लागू होगी
7(छ)	आकाशी यात्री रज्जुमार्ग		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
7(ज)	सामान्य स्राव उपचार संयंत्र (स.स.उ.सं.)		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
7(झ)	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा (स.न.अ.प्र.स.)		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
8	मवन/संनिर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण			
8(क)	मवन एवं संनिर्माण परियोजनाएं		≥ 20000 वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र और < 1.50,000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र #	# आवृत संनिर्माण के लिए निर्मित क्षेत्र आकाश की ओर खुली सुविधाओं की दशा में यह क्रियाकलाप क्षेत्र भी होगा।
8(ख)	नगरी और क्षेत्र विकास परियोजनाएं		≥ 50 हे० क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए और या निर्मित क्षेत्र ≥ 1,50,000 वर्ग मीटर ++	++ 8 (ख) के अंतर्गत सभी परियोजनाओं को ख 1 प्रबन्ध के अनुसार निर्बंधित किया जाएगा।

टिप्पण

साधारण शर्त (सा.श.)

प्रबन्ध "ख" में विनिर्दिष्ट किसी परियोजना या क्रियाकलाप को प्रबन्ध "क" माना जाएगा, यदि वह : (i) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र; (ii) उसकी समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है; (iii) परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित है; और (iv) अंतरराज्यिक सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से दस किलोमीटर के भीतर संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप में अवस्थित है।

विनिर्दिष्ट शर्त (वि.श.)

यदि कोई मद 4(घ), 4(च), 5(ड), 5(च) जैसी समयुक्त की प्रकार का उद्योगों वाले औद्योगिक संपदा/कांप्लेक्स/निर्यात प्रसंस्करण जोन/विशेष आर्थिक जोन/जैव प्रौद्योगिकी उद्यान/घमड़ा परिसर या पूर्व निर्धारित गतिविधियां वाले उद्योग (आदर्शगत नहीं कि वे समयुक्त हों) पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करते हैं, तो ऐसी संपदाओं/कांप्लेक्सों के भीतर प्रस्तावित उद्योगों सहित निजी उद्योगों को तब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेना अपेक्षित नहीं है जब तक कि औद्योगिक कांप्लेक्स/संपदा के लिए निबंधनों और शर्तों का अनुपालन नहीं करते (ऐसी संपदा/कांप्लेक्सों की पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की निबंधनों और शर्तों के लिए सहमता सुनिश्चित करने के विधिक उत्तरदायित्व से स्पष्ट रूप से पहचान करने का प्रबंध होना चाहिए जिसे कांप्लेक्स/संपदा के सारे जीवन में उसके अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा)।

[सं. जे-11013/56/2004-आईए-11(i)]

आर. चंद्रमोहन, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट -I  
(पैरा 6 देखें)  
प्रारूप 1

## (1) आधारभूत जानकारी

परियोजना का नाम :  
विद्यार्थी अनुकूल अवस्थिति/स्थान :  
परियोजना का आकार :  
परियोजना की प्राक्कलित लागत :  
संपर्क जानकारी :  
संवीक्षा प्रवर्ग :

- अचलीय क्रियाकलाप के लिए तत्स्थानी क्षमता (जैसे विनिर्माण करने के लिए उत्पादन क्षमता, खनिज उत्पादन के लिए खनन पट्टा क्षेत्र और उत्पादन क्षमता, खनिज पूर्वक्षण के लिए क्षेत्र, अनुरेख परिवहन अवसंरचना के लिए लंबाई, विद्युत उत्पादन आदि के उत्पादन क्षमता )

## (ii) क्रियाकलाप

1. परियोजना का संनिर्माण, प्रचालन या न निकालना जिसमें ऐसी कार्यवाही भी सम्मिलित है जो परिक्षेत्र में भौतिक परिवर्तनों का कारण होगी (स्थलाकृति, भूमि उपयोग, जल निकासों में परिवर्तन आदि)

क्र.सं.	जानकारी/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	उनके ब्यौरे (लगभग मात्रा/दरों, सहित, जो संभव हो, सहित) आंकड़ों की जानकारी के स्रोत सहित।
1.1	भूमि उपयोग, समावेश भूमि या स्थलाकृति में स्थायी या अस्थायी ढंग में भूमि उपयोग की मात्रा (स्थानीय भूमि उपयोग योजना के बारे में वृद्धि भी सम्मिलित है)		
1.2	विद्यमान भूमि, वनस्पति और भवनों की अनापत्ति		
1.3	नई भूमि उपयोगों का सृजन		
1.4	संनिर्माण पूर्व अन्वेषण अर्थात् बोर गृह, मिट्टी का परिक्षण करना		
1.5	संनिर्माण कार्य		
1.6	विध्वंस कार्य		

1.7	संनिर्माण कार्य या संनिर्माण कर्मकारों के घर के प्रबंध के लिए उपयोग किए गए अस्थायी स्थल.		
1.8	उपर्युक्त भू-भवन, संरचनाएं या घुस्स जिसमें अनुरेखीय संरचनाएं, काटना और भरना या खुदाई भी सम्मिलित है।		
1.9	भूमिगत कार्य जिसमें खनन या सुरंग बनाना भी सम्मिलित है।		
1.10	भूमि उद्धार कार्य		
1.11	तलकषक		
1.12	अपतट संरचनाएं		
1.13	उत्पादन और विनिर्माण प्रक्रियाएं		
1.14	सामग्रियों या माल के भंडार की सुविधाएं		
1.15	ठोस अपशिष्ट या तरल बहिःस्रावों के उपचार या निपटान के लिए सुविधाएं		
1.16	परिचालन कर्मकारों के दीर्घकालिक घर के प्रबंध के लिए सुविधाएं		
1.17	संनिर्माण या प्रचालन के दौरान नई सड़क, रेल या समुद्री यातायात		
1.18	नई सड़क, रेल, वायु जल वाहित या अन्य परिवहन अवसंरचना जिसमें नए या परिवर्तित मार्ग और स्टेशन, पत्तन, विमानपत्तन आदि भी सम्मिलित है।		
1.19	विद्यमान परिवहन मार्गों को बंद करना या अपवर्तन या यातायात परिचालन में परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त अवसंरचना		
1.20	नई या अपवर्तित प्रेषण लाइनें या पाइपलाइनें		
1.21	अवरुद्ध करना, बांध बनाना, पुलिया बनाना, पुनःरेखांकन या जलमार्गों या एक्वीकरों के जल विज्ञान के लिए अन्य परिवर्तन		
1.22	प्रवाह पार		
1.23	भूजल या भूतल से जल का अंतरण या पृथक्करण		
1.24	नालियों या प्रवाह को प्रभावित करने वाले जलनिष्पादों या भूमि स्तर में परिवर्तन		
1.25	संनिर्माण, परिचालन या न निकालने के लिए कार्मिक या सामग्रियों का परिवहन		
1.26	दीर्घकालिक रूप में तोड़ना, प्रारंभ करना या कार्य पुनः आरंभ करना।		
1.27	आरंभ के दौरान जारी ऐसे क्रियाकलाप जो पर्यावरण पर संभावित कर सकेंगे।		
1.28	जनता का, किसी क्षेत्र के लिए या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से आना।		
1.29	अन्य देशीय प्रजातियों का आना		
1.30	मूल निवासी प्रजातियों या आनुवंशिक विविधता की हानि		
1.31	अन्य कोई कार्रवाईयां		

2. परियोजना के संनिर्माण या प्रचालन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग (जैसे भूमि, जल सामग्री या ऊर्जा विशेष रूप से ऐसा कोई संसाधन जो नवीकरणीय नहीं है या जिसका प्रदाय कम है)

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुरीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यारे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
2.1	विशेष रूप से अविकसित भूमि या कृषि भूमि (है)		
2.2	जल (अनुमानित स्रोत और प्रतियोगी उपयोगकर्ता) इकाई के एल.डी.		
2.3	खनिज (एम.टी.)		
2.4	परिष्कार सामग्री - बाल्टर औरण, कंकड़/मृदा (अनुमानित स्रोत एम.टी.)		
2.5	ठस और इनकी लकड़ी (स्रोत एम.टी.)		
2.6	सभी किसके अंतर्गत विद्युत और ईंधन (स्रोत, प्रतियोगी उपयोगकर्ता) इकाई : ईंधन (एम.टी.) ऊष्मा (एम.किल्यू)		
2.7	कोई अन्य प्राकृतिक संसाधन (समुचित मानक इकाईयों का उपयोग करें)		

3. मृदा या सामग्रियों का उपयोग, परिवहन, जलाई या उत्पादन, जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरनाक या जिनके मानव स्वास्थ्य को जोखिम की भावनायिकता के बारे में चिंताएं उठती हैं।

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुरीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यारे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
3.1	मनसई या सामग्रियों का उपयोग जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण (फ्लोरा, फोसा और जल प्रदाय के लिए परिष्कारकर्ता) एम.एल.आइ.एच.सी. नियमों के अनुसार हैं		
3.2	संग्रहण में परिवर्तन या रोग वाहकों के रोग का प्रभाव (उपह्वलनायक कीट या जल-जन्म रोग)		
3.3	संग्रहण के कारण पर परत उपह्वलनायक जीवन दशाओं में परिवर्तन करके		
3.4	संग्रहण के संचयनशील समूह जो परियोजना अर्थात् अस्पताल रोगियों, बालकों, वृद्धों आदि द्वारा प्रभावित हो सकते हैं		
3.5	कोई अन्य कारण		

179

4. निर्माण या प्रचालन या प्रारंभ न करने के दौरान ठोस अपशिष्टों का उत्पादन (एम.टी./मस)

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के साथ-साथ उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहाँ कहीं संभव हो)
4.1	मृदा, अधिक नार या खान अपशिष्ट		
4.2	नगरपालिक अपशिष्ट (घरेलू और या वाणिज्यिक अपशिष्ट)		
4.3	परिसंकटमय अपशिष्ट (परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंध तंत्र नियमों के अनुसार)		
4.4	अन्य औद्योगिक प्रक्रिया अपशिष्ट		
4.5	अधिशेष उत्पाद		
4.6	मल बही-खाव उपचार से मल गाद या अन्य गाद		
4.7	निर्माण या ढाये गए अपशिष्ट		
4.8	बेकार मशीनरी या उपकरण		
4.9	संदूषित मृदाएं या अन्य सामग्रियां		
4.10	कृषि अपशिष्ट		
4.11	अन्य ठोस अपशिष्ट		

5. वायु में संदूषकों या किसी परिसंकटमय विषयों या मशीनों/उद्योगों का विसर्जन

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के साथ-साथ उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहाँ कहीं संभव हो)
5.1	खोखल सामग्री या चल संसाधनों से जीवाणु इंधनों के दहन से उत्सर्जन		
5.2	उत्पादन प्रक्रियाओं से उत्सर्जन		
5.3	सामग्रियों की उठाई धराई से जिसके अंतर्गत भंडारण या परिवहन भी है उत्सर्जन		
5.4	निर्माण क्रियाकलापों से जिसके अंतर्गत संयंत्र और उपकरण भी हैं उत्सर्जन		
5.5	सामग्रियों की उठाई धराई से जिसके अंतर्गत निर्माण सामग्री, मल और अपशिष्ट भी हैं धूल या मंद		
5.6	अपशिष्ट के मस्मीकरण से उत्सर्जन		
5.7	खुली वायु में अपशिष्ट के प्रदूषण से उत्सर्जन (उदाहरणार्थ मल, कचरा, निर्माण सामग्री का धूल)		
5.8	किसी अन्य स्रोतों से उत्सर्जन		

6. शोर और कंपन का पैदा होना तथा प्रकाश और उष्मा का उत्सर्जन

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
6.1	उपस्कर के प्रचालन से उदाहरणार्थ ईजन, वातायन संयंत्र, संदलनित्र		
6.2	औद्योगिक या उसी प्रकार की प्रक्रियाओं से		
6.3	निर्माण या ढहाने से		
6.4	विस्फोटन या पाइलिंग से		
6.5	निर्माण या प्रचालन संबंधी शतायात से		
6.6	प्रकाशन या प्रशीतन प्रणालियों से		
6.7	किन्हीं अन्य संसाधनों से		

7. भूमि या मल नालियों, सतही जल, भूमिगत जल, तटीय जल या समुद्र में प्रदूषकों के विसर्जन से भूमि या जल के संदूषण के जोखिम

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
7.1	परिसंकटमय सामग्री की उठाई धराई, भंडारण, उपयोग या गाद से		
7.2	जल या भूमि में (अनुमानित दंग और विसर्जन का स्थान) मल या अन्य बड़ी मात्राओं के विसर्जन से		
7.3	वायु से भूमि या जल में उत्सर्जित प्रदूषकों के जमा होने से		
7.4	किन्हीं अन्य संसाधनों से		
7.5	क्या इन संसाधनों से पर्यावरण में प्रदूषकों के जमा होने से दीर्घकालिक जोखिम है ?		

8. परियोजना के निर्माण या प्रचालन के दौरान दुर्घटनाओं का जोखिम जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित जहां कहीं संभव हो)
8.1	परिसंकटमय पदार्थों के विस्फोट, गाद, आग, भंडारण, उठाई धराई या उत्पादन से		
8.2	किन्हीं अन्य कारणों से		
8.3	क्या परियोजना प्राकृतिक विपदाओं द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगी (उदाहरणार्थ बाढ़, भूकंप, भू-सखलन, वृष्टिस्फोट आदि) ?		

9. बातें जिन पर विचार किया जाना चाहिए (जैसे पारिस्थितिक विकास) जिनके कारण पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं या जो संचयी प्रभावों को करने के लिए अन्य विद्यमान प्रभावों सहित या परिक्षेत्र में नियोजित क्रियाकलापों के लिए सामर्थ्यवान हैं

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके बारे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
9.1	जिसके कारण आधार का विकास, सहायक विकास या परियोजना द्वारा विकास को बल मिलता है जिसका पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है अर्थात् — • आधुनिक अवसंरचना (सड़कें, बिजली प्रदाय, अपशिष्ट या अपशिष्ट जल उपचार आदि) • आवासन विकास • निष्कर्षित उद्योग • पूर्ण उद्योग • अन्य		
9.2	जिसके कारण स्थल का बाद में उपयोग होता है जिसका पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है		
9.3	पर्यावरणीय विकासों के लिए उदाहरण स्थापित करना		
9.4	सामूहिक के कारण अन्य विद्यमान परियोजनाओं पर संचयी प्रभाव हैं या उसी प्रकार के प्रभावों सहित नियोजित परियोजनाएं		

## (III) पर्यावरणीय संवेदनशीलता

क्र.सं.	क्षेत्र	नाम/पहचान	आकाशी दूरी (15 किलोमीटर के भीतर) प्रस्तावित परियोजना अवस्थान सीमा
1.	उनके पारिस्थितिक भू-दृश्य, सांस्कृतिक या अन्य संबंधित मूल्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन, राष्ट्रीय या स्थानीय विधान के अधीन संरक्षित क्षेत्र।		
2.	क्षेत्र जो पारिस्थितिक कारणों के लिए महत्वपूर्ण या संवेदनशील हैं - बेट लैंड्स, जल स्रोत या अन्य जल संबंधी निकाय, तटीय जोन, बायोस्फीयर, पहाड़ियां, वन		
3.	क्षेत्र जो प्रजनन, घासला बनाने, चारे के लिए, आश्रय करने के लिए, सर्दियों के लिए, प्रवास के लिए फलों और फोंना के संरक्षित महत्वपूर्ण या संवेदनशील प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं		
4.	अंतरराष्ट्रीय, तटीय, सामुद्रिक या भूमिगत जल		

5.	राज्य, राष्ट्रीय सीमाएं		
6.	मनोरंजन की या अन्य पर्यटक/यात्रियों वाले क्षेत्रों में पहुंच के लिए जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्ग या सुविधाएं		
7.	रक्षा प्रतिष्ठापन		
8.	राधन रूप से बसे हुए या निर्मित क्षेत्र		
9.	शेवदनशील मानव निर्मित भूमि उपयोगों के अधिभोगापीन क्षेत्र अस्पताल, पाठशालाएं, पूजा स्थल, सामुदायिक सुविधाएं		
10.	महत्वपूर्ण, उच्च क्वालिटी या दुर्लभ संसाधनों वाले क्षेत्र (भूमिगत जल संसाधन, भूतल संसाधन, वनोद्योग, कृषि, मत्स्य उद्योग, पर्यटन, खनिज)		
11.	क्षेत्र जो पहले से ही प्रदूषण या पर्यावरणीय दुकसान के अधीन है (वे जहां विद्यमान विधिक पर्यावरणीय मानक अधिक होते हैं)		
12.	क्षेत्र जहां प्राकृतिक संकट हो सकता है जो वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं की योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं (धंसना, भूस्खलन, भूमि कटाव, बाढ़ या अत्यंत या प्रतिकूल वातावरणीय दशाएं)		

परिशिष्ट 2  
(पैरा 6 देखें)

प्ररूप 1क (केवल अनुसूची की मद 8 के अधीन सूचीबद्ध निर्माण परियोजनाओं के लिए)

पर्यावरणीय प्रभावों की जांच सूची

(पूर्ण जानकारी उपलब्ध कसाने के लिए अपेक्षित परियोजना सलाहकार और जहां कहीं आवश्यक हो प्ररूप के साथ स्पष्टीकारक, टिप्पण संलग्न करें तथा प्रस्तावित पर्यावरणीय पर्यवेक्षण योजना और मानिटीरी कार्यक्रम के रतन प्रस्तुत करें)

1. भूमि पर्यावरण

(परियोजना स्थल और आसपास का दिशात दूरय संलग्न करें)

1.1 क्या विद्यमान भूमि के उपयोग में परियोजना से सम्बन्धन रूप से परिवर्तन किया जाएगा जो वातावरण आसपास से संगत नहीं है ? (प्रस्तावित भूमि उपयोग सभ्य प्राधिकारी के अनुमोदित वास्तु/विकास योजना के अनुरूप होना चाहिए। भूमि उपयोग में परिवर्तन यदि कोई हो और सभ्य प्राधिकारी से कानूनी अनुमोदन प्रस्तुत किया जाए) : (i) स्थल अवस्थान, (ii) प्रस्तावित स्थल (पंच सौ मीटर के भीतर आसपास के सभ्यभों) और (iii) समुचित वास्तुमान से स्थल (रतन और सभ्य रेखा उपदर्शित कलते हुए) के अर्थ में संलग्न करें। यदि उपलब्ध नहीं है तो केवल अवधारणा तुल्य योजना संलग्न करें।

1.2 भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, जल सभ्यीय, विद्युत आपूर्ति, सभ्यीयकलन, सामुदायिक सुविधाएं, आवागमन/मार्ग प्रभों के अनुसार सभ्य बड़ी परियोजना की आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करें।

1.3 प्रस्तावित स्थल से संलग्न विद्यमान सुविधाओं पर प्रस्तावित विकास/संशोधन के कारण, प्रभाव, जो कि सभ्य सुले स्थल, सामुदायिक सुविधाएं, विद्यमान भूमि उपयोग के अर्थ में, रतन दिव्य परिशिष्टित आसपास।

1.4 जल विषयी महत्वपूर्ण भूमि सभ्य के परिभाषित/संरक्षण प्रस्तावित भूमि कटाव या अतिरिक्त कलन से सभ्य सभ्य, अल सभ्य, भूमि कटाव की संकेत/संकेतक संलग्न करने के अर्थ में प्रस्तुत करें।



- 1.5 क्या प्राकृतिक मूल विकास प्रणाली के परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव है ? (प्रस्तावित परियोजना स्थल के निकट प्राकृतिक मूल विकास को दर्शाते हुए किसी समोच्च नक्शे के ब्यारे दें)
- 1.6 निर्माण क्रियाकलाप — कर्तव्य, भरण, भूमि सुधार आदि में अंतर्वर्तित भूमि कार्य की मात्राएं क्या हैं ? (अंतर्वर्तित भूमि कार्य, स्थल आदि के बाहर से सामग्री भरने के परिवहन के ब्यारे दें)
- 1.7 निर्माण अवधि के दौरान जल प्रदाय अप्रशिष्ट उठाई धराई आदि के संबंध में ब्यारे दें ।
- 1.8 क्या नीचे के क्षेत्रों और वेट लैंड्स में परिवर्तन होने ? (बड़े ब्यारे दें कि, किस प्रकार निचले क्षेत्र और वेट लैंड्स प्रस्तावित क्रियाकलापों से उपांतरित हो रहे हैं)
- 1.9 क्या निर्माण के दौरान निर्माण के कूड़ा करकट और अपशिष्ट से स्वास्थ्य को खतरा होगा ? (निर्माण के दौरान जिराके अंतर्गत निर्माण श्रम और व्यय की सुविधाएं भी हैं, जिनसे अपशिष्टों की विभिन्न किस्मों की मात्राएं दें ।)
2. जल पर्यावरण
- 2.1 विभिन्न उपयोगों की अपेक्षाओं के विश्लेषण सहित प्रस्तावित परियोजना के लिए जल अपेक्षा की कुल मात्रा दें । जल अपेक्षा की पूर्ति कैसे होगी । स्रोतों और मात्राओं का अथन करें तथा एक जल अतिशेष विवरण दें ।
- 2.2 जल के प्रस्तावित स्रोत की क्षमता क्या है ? (बहाव या प्राप्ति के आधार पर)
- 2.3 अपेक्षित जल की क्वालिटी क्या है यदि पूर्ति किसी नगर पालिक स्रोत से नहीं है ? (जल की क्वालिटी के वर्ग सहित भौतिक, रासायनिक जैव वैज्ञानिक लक्षणों को तर्जित करें)
- 2.4 कितनी जल अपेक्षा की उपचारित वेधर जल के पुनः प्रयोग से पूर्ति हो सकती है ? (मात्राओं, स्रोतों और उपयोगिताओं के ब्यारे दें ।)
- 2.5 क्या अन्य उपयोगताओं से जल का उपयोग होगा ? (कृषक अन्य विद्यमान उपयोगों और उपभोग की मात्राओं पर परियोजना के प्रभाव का निर्धारण करें)
- 2.6 प्रस्तावित क्रियाकलापों से प्राप्त वेधर जल से प्रदूषण के भार से क्या वृद्धि है ? (प्रस्तावित क्रियाकलापों से प्राप्त वेधर जल की मात्राओं और संघटन के ब्यारे दें)
- 2.7 जल अपेक्षाओं की जल संवयन से हुई पूर्ति के ब्यारे दें । सृजित सुविधाओं के ब्यारे प्रस्तुत करें ।
- 2.8 दीर्घकालिक आधार पर निर्माण चरण के परवात् क्षेत्र की प्रस्तावित परियोजना के पूरा होने के लक्षणों (मात्रात्मकता के साथ-साथ क्वालिटी भी) के कारण भूमि उपयोग में हुए परिवर्तनों का क्या प्रभाव होगा ? क्या इससे बाढ़ या जल के जमा होने की किसी रूप में सम्भ्रमा में वृद्धि होगी ?
- 2.9 भूमिगत जल पर प्रस्ताव के क्या प्रभाव होंगे ? (क्या भूमिगत जल में गलत सामग्री जाएगा ? भूमिगत जल की स्तरणी, पुनः प्रभारण क्षमता और सक्षम प्राधिकारों से अधिग्रहण अनुमति यदि कोई हो के ब्यारे दें)
- 2.10 भूमि और पनिले को प्रदूषित करने वाले निर्माण क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त सावधानियां/क्याम उपाय होंगे ? (प्रदूषण प्रकृतिक संसाधनों के क्षति को रोकने के लिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उपायों के ब्यारे दें)

5.4 प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन क्षेत्रों में आंतरिक सड़कों, बाइसिकिल मार्गों, पैदल यात्री मार्गों, पैदल मार्गों आदि पर चलने के पैटर्न के ब्यारे दें।

5.5 क्या यातायात शोर और कंपन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी ? उम्र वर्णित बातों को कम करने के लिए स्रोतों और प्रस्तावित उपायों के ब्यारे दें।

5.6 परियोजना स्थल के आसपास शोर इतने और कंपन तथा धिरी हुई वायु की क्यालिटी पर डीजी सेटों और अन्य उपकरणों पर क्या प्रभाव होगा ? ब्यारे दें।

#### 6. सौन्दर्यबोद्धी

6.1 क्या प्रस्तावित निर्माणों के परिणामस्वरूप किसी दृश्य, दृश्यसुविधा या भूदृश्य में स्क्राबट होगी ? क्या प्रस्तावको ने इन बातों पर विचार कर लिया है ?

6.2 क्या विद्यमान परिनिर्माणों पर नए निर्माण से कोई प्रतिकूल प्रभाव होगा ? किन बातों को ध्यान में रखा गया है ?

6.3 क्या डिजाइन मापमान को प्रभावित करने वाले शहर रूमी या शहरी डिजाइनों का कोई स्थानीय आकलन है ? उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा सकता है।

6.4 क्या कोई मानव विज्ञान संबंधी या पुरातत्वीय स्थल या बाह्य चीजें आसपास में हैं ? कथन करें यदि कोई अन्य महत्वपूर्ण बात, जिसपर प्रस्तावित स्थल के परिक्षेत्र में होने पर विचार किया गया है।

#### 7 सामाजिक - आर्थिक पहलू

7.1 क्या प्रस्ताव के परिणामस्वरूप स्थानीय जनता के समाज संबंधी परिनिर्माणों में कोई परिवर्तन होगा ? ब्यारे दें।

7.2 प्रस्तावित परियोजना के आसपास विद्यमान सामाजिक अवसरचना के ब्यारे दें।

7.3 क्या परियोजना से स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव, पवित्र स्थलों या अन्य सांस्कृतिक मूल्यों में विध्वंस पड़ेगा ? प्रस्तावित सुरक्षापाय क्या हैं ?

#### 8 निर्माण सामग्री

8.1 अधिक ऊर्जा संहित निर्माण सामग्री का उपयोग हो सकेगा। क्या ऊर्जा दक्ष प्रक्रियाओं सहित निर्माण सामग्री उत्पादित की जाती है ? (निर्माण सामग्री और उनकी ऊर्जा दक्षता का चयन करने में ऊर्जा संरक्षण उपायों के ब्यारे दें)

8.2 निर्माण के दौरान सामग्री का परिवहन और उलाई धराई के कारण प्रदूषण, शोर और लोक अशान्ति हो सकती है। इन प्रभावों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाने हैं ?

8.3 क्या सड़कों और ढांचों में पुनः चक्रित सामग्री उपयोग की जाती है ? की गई बचतों का सीमा का कथन करें ?

8.4 परियोजना के प्रचालन संबंधी चरणों के दौरान हुए कूड़े के संग्रहण, पृथक्करण और ध्यान की पहलु के ब्यारे दें।

परिशिष्ट 3  
(पैरा 7 देखें)

## पर्यावरणीय समाघात निर्धारण दस्तावेज की साधारण संरचना

क्र.सं.	ईआईए संरचना	अंतर्वस्तु
1.	प्रारम्भिक	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रिपोर्ट का प्रयोजन</li> <li>• परियोजना और परियोजना प्रस्तावक की पहचान</li> <li>• परियोजना की प्रकृति, आकार, अवस्थान का संक्षिप्त वर्णन और देश, प्रदेश में इसका महत्व</li> <li>• अध्ययन का विस्तार -- किए गए विनियामक विस्तार के ब्यौरे (सॉपे गए कृत्यों के अनुसार)</li> </ul>
2.	परियोजना वर्णन	<ul style="list-style-type: none"> <li>• परियोजना के उन पहलुओं का संघनित वर्णन (परियोजना साध्यता अध्ययन पर आधारित) जिनकी पर्यावरणीय प्रभाव कांति करने की संभावना है। निम्नलिखित को स्पष्ट करने के लिए ब्यौरे उपबंधित किए जाने चाहिए :</li> <li>• परियोजना के किस्म</li> <li>• परियोजना की आवश्यकता</li> <li>• अवस्थान (साधारण अवस्थान, विनिर्दिष्ट अवस्थान, परियोजना सीमा और परियोजना स्थल अभिन्यास को दर्शित करते हुए नक्शे)</li> <li>• प्रबंधन का आकार या विस्तार (जिसके अंतर्गत परियोजना द्वारा या उसके लिए अपेक्षित सहयोजित क्रियाकलाप)</li> <li>• अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित अनुसूची</li> <li>• प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया वर्णन</li> <li>• परियोजना वर्णन, जिसके अंतर्गत परियोजना अभिन्यास, परियोजना आदि के संघटकों को दर्शित करते हुए आरेखन। साध्यता आरेखनों के स्कीमबद्ध प्रतिनिधित्व, जो ईआईए परियोजना के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दें।</li> <li>• पर्यावरणीय मानकों, पर्यावरणीय प्रचालन दशाओं या अन्य ईआईए अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए परियोजनाओं में सम्मिलित न्युनिवारण उपायों का वर्णन (विस्तार द्वारा यथाअपेक्षित)</li> <li>• प्रौद्योगिकीय असफलता के जोखिम के लिए नई और अपरीक्षित प्रौद्योगिकी का निर्धारण</li> </ul>
3.	पर्यावरण का वर्णन	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अध्ययन क्षेत्र, अवधि, संघटक और पद्धति</li> <li>• विस्तार में पहचान किए गए मूल्यवान पर्यावरणीय संघटकों के लिए आधारिक लेखा की स्थापना</li> <li>• सभी पर्यावरणीय संघटकों के आधार नक्शे</li> </ul>
4.	अनुमानित पर्यावरणीय समाघात और न्यूनीकरण उपाय	<ul style="list-style-type: none"> <li>• परियोजना अवस्थान, संभावित दुर्घटनाओं, परियोजना डिजाइन, परियोजना निर्माण, नियमित प्रचालनों, पूरी की गई परियोजना को अंतिम रूप से बंद करना या पुनर्स्थापन के कारण अन्वेषित पर्यावरणीय समाघातों के ब्यौरे।</li> <li>• पहचान किए गए प्रतिकूल समाघातों न्यूनिकृत और/या दूर करने के लिए उपाय</li> <li>• पर्यावरणीय संघटकों के अंतर्परिवर्तनीय और पुनः प्राप्त न किए जा सकने वाले आशवासन।</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>समाघातों के महत्व का निर्धारण (महत्व महत्व निर्धारण का अवधारणा करने के लिए मानदण्ड)</li> <li>न्यूनीकरण उपाय</li> </ul>
5.	अनुकल्पियों का विश्लेषण (प्रौद्योगिकी और स्थल)	<ul style="list-style-type: none"> <li>यदि विस्तारित करने के कार्य के परिणामस्वरूप अनुकल्पियों की आवश्यकता होती है</li> <li>प्रत्येक अनुकल्पी का वर्णन</li> <li>प्रत्येक अनुकल्पी के प्रतिकूल समाघातों का सार</li> <li>प्रत्येक अनुकल्पी के लिए प्रस्तावित न्यूनीकरण उपाय और अनुकल्पी का ध्यान</li> </ul>
6.	पर्यावरणीय मानिटर कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> <li>न्यूनीकरण उपायों की प्रभावशीलता को मानीटर करने के तकनीकी पहलू (जिसके अंतर्गत माप, पहचान, आवर्त, अवस्थान, आंकड़े विश्लेषण, रिपोर्ट करने की अनुसूचियां, आपात प्रक्रियाएं, विस्तृत बजट और उपायन अनुसूचियां भी हैं)</li> </ul>
7.	अतिरिक्त अध्ययन	<ul style="list-style-type: none"> <li>लोक परामर्श</li> <li>जोखिम निर्धारण</li> <li>सामाजिक समाघात निर्धारण आर और आर अनुवर्ती योजनाएं</li> </ul>
8.	परियोजना के फायदे	<ul style="list-style-type: none"> <li>भौतिक अवसंरचना में सुधार</li> <li>सामाजिक अवसंरचना में सुधार</li> <li>नियोजन क्षमता - कुशल ; अर्धकुशल और अकुशल</li> <li>अन्य मूल फायदे</li> </ul>
9.	पर्यावरणीय लागत फायदा विश्लेषण	यदि विस्तारण प्रक्रम पर सिफारिश की जाती है ।
10.	ईएमपी	<ul style="list-style-type: none"> <li>यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यूनीकरण संबंधी उपाय कार्यान्वित किए गए हैं और ईआईए के अनुमोदन के प्रभाव उनकी प्रभावी मानीटर की गई है, प्रशासनिक पहलुओं का वर्णन ।</li> </ul>
11.	संक्षिप्त सार और निष्कर्ष (यह ईआईए रिपोर्ट का संक्षिप्त सार होगा)	<ul style="list-style-type: none"> <li>परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समय अतिरिक्त ।</li> <li>यह स्पष्टीकरण कि प्रतिकूल प्रभाव किस प्रकार कम किए जाते हैं</li> </ul>
12.	नियोजित परामर्शियों का प्रकटन	<ul style="list-style-type: none"> <li>उनके संक्षिप्त कार्य और दिए गए परामर्श की प्रकृति सहित नियोजित किए गए परामर्शियों के नाम</li> </ul>

परिशिष्ट 3क

(पेज 7 देखें)

संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की अंतर्वस्तु

पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का संक्षिप्त सार अधिकतम ए-4 आकार के उस पृष्ठों पर पूरी पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का एक संक्षिप्त सार होगा । इसमें संक्षेप में अनिवार्य रूप से पूर्ण पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निम्नलिखित अध्याय होने चाहिए :-

- (1) परियोजना वर्णन ;
- (2) पर्यावरण का वर्णन ;
- (3) अनुमानित पर्यावरणीय समाघात और न्यूनीकरण उपाय ;
- (4) पर्यावरणीय मानीटर कार्यक्रम ;
- (5) अतिरिक्त अध्ययन ;
- (6) परियोजना के फायदे ;
- (7) पर्यावरण प्रबंधन योजना ;

## परिशिष्ट 4

(पैरा 7 देखिए)

लोक सुनवाई को संचालित करने के लिए प्रक्रिया:

1.0 लोक सुनवाई की, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा परियोजना स्थल (स्थलों) में या उसके निकटस्थ परिसर में जिला वार एक प्रणालीबद्ध, समयबद्ध और पारदर्शी रीति में अधिकतम संभव लोक भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए व्यवस्था की जाएगी।

2.0 प्रक्रिया :

2.1 आवेदक, उस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव को, जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित है, विहित कानूनी अवधि के भीतर लोक सुनवाई की व्यवस्था करने के लिए एक सादा पत्र के माध्यम से अनुरोध करेगा। यदि परियोजना स्थल का किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के परे विस्तार है तो प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जिसमें परियोजना स्थित है, लोक सुनवाई आज्ञापक है और आवेदक, इस प्रक्रिया के अनुसार लोक सुनवाई करने के लिए प्रत्येक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को पृथक अनुरोध करेगा।

2.2 आवेदक, अनुरोध पत्र के साथ प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की कम से कम दस हार्ड प्रतियां और उसी के बराबर सॉफ्ट (इलेक्ट्रॉनिक) प्रतियां, परिशिष्ट 3 में दी गई सामान्य संरचना सहित (जिसके अंतर्गत विस्तार (प्रक्रम 2) के पश्चात् संसूचित किए गए सीधे सर कृत्यों के अनुसार निर्वाध रूप से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में तैयार की गई संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट सम्मिलित है) संलग्न की जाएगी। इसके साथ-साथ आवेदक संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ ऊपर प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक हार्ड प्रति और एक सॉफ्ट प्रति पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा निम्नलिखित प्राधिकारियों या कार्यालयों की जिनकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित होगी, अंग्रेषित करने की व्यवस्था करेगा :

(क) जिला मजिस्ट्रेट

(ख) जिला परिषद या नगर निगम

(ग) जिला उद्योग कार्यालय

(घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय का संबंधित प्रादेशिक कार्यालय

2.3 उपर उल्लिखित प्राधिकारी, पर्यावरण और वन मंत्रालय के सिवाय, प्रारम्भ पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट का प्राप्ति पर अपनी अधिकारिताओं के भीतर उसमें हितवद् व्यक्तियों से संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को अपनी टीका-टिपणियां भेजने का अनुरोध करते हुए, विस्तृत प्रचार करने की व्यवस्था करेंगे। वे लोक सुनवाई होने तक सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान जनता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा निरीक्षण करने के लिए प्रारम्भ पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएंगे। पर्यावरण और वन मंत्रालय अपनी वेबसाइट पर प्रारम्भ पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार तत्परता से प्रदर्शित करेगा और दिल्ली स्थित मंत्रालय में सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान किसी अधिसूचित स्थान पर निर्देश के लिए पूरे प्रारम्भ पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट को भी उपलब्ध कराएगा।

2.4 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के भीतर परियोजना की वास्तव प्रचार करने के लिए उसी प्रकार की व्यवस्था करेंगी और नियमित कार्यालयों या लोक पुस्तकालयों या पंचायतों आदि में निरीक्षण के लिए प्रारम्भ पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट (परिशिष्ट 3क) का संक्षिप्त सार उपलब्ध कराएगी। वे उपर्युक्त पांच प्राधिकारियों/कार्यालयों अर्थात् पर्यावरण और वन मंत्रालय, जिला मजिस्ट्रेट आदि को प्रारम्भ पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति अतिरिक्त रूप से भी उपलब्ध कराएंगे।

### 3.0 लोक सुनवाई की सूचना

3.1 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य सचिव परियोजना सलाहकार से प्रारम्भ पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर लोक सुनवाई संघसित करने के लिए तारीख, समय और विशिष्ट स्थान को अंतिम रूप देगा और उसको मुख्य राष्ट्रीय दैनिक में और एक प्रादेशिक भाषा के दैनिक समाचारपत्र में विज्ञापित करेगा। जनता को अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए कम से कम तीस दिनों की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

3.2 विज्ञापन, जनता को उन स्थानों या कार्यालयों की वास्तव भी सूचित करेगा जहां प्रारम्भ पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार लोक सुनवाई से पूर्व जनता की पहुंच हो सके।

3.3 लोक सुनवाई की तारीख, समय और स्थान को तब तक आस्थगित नहीं किया जाएगा जब तक कोई अवशिष्ट आपात स्थिति न आ जाए और केवल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर किया आस्थगन को उन्हीं राष्ट्रीय और प्रादेशिक भाषा के समाचार पत्रों के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पहचान किए सभी कार्यालयों में मुख्य रूप से प्रदर्शित भी किया जाएगा।

3.4. उमर आपवादिक परिस्थितियों में, केवल जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य-सचिव द्वारा, लोक परामर्श के लिए नई तारीख, समय और स्थान का विनिश्चय किया जाएगा और उमर 3.1 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार नए सिरे से अधिसूचित किया जाएगा।

#### 4.0 पैनल

जिला मजिस्ट्रेट या किसी अपर जिला मजिस्ट्रेट से अन्यून की पंक्ति का उसका प्रतिनिधि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि की सहायता से समस्त लोक सुनवाई प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा।

#### 5.0 वीडियोग्राफी

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, समस्त कार्यवाहियों की वीडियो फिल्म तैयार करने की व्यवस्था करेगी। संबंधित विनियामक प्राधिकरण को इसे अंग्रेजित करते, समय वीडियो टेप की एक प्रति या एक सीडी लोक सुनवाई कार्यवाहियों के साथ संलग्न की जाएगी।

#### 6.0 कार्यवाहियाँ

6.1 उन सभी व्यक्तियों की उपस्थिति को जो स्थल पर विद्यमान हैं, अंतिम कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा।

6.2 कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए उपस्थिति हेतु कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी।

6.3 आवेदक का कोई प्रतिनिधि, परियोजना और पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार की प्रस्तुति के साथ कार्यवाहियाँ आरंभ करेगा।

6.4 स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को, आवेदक से परियोजना पर सूचना या स्पष्टीकरण मांगने का अवसर दिया जाएगा। लोक सुनवाई कार्यवाहियों का संक्षिप्त सार ठीक रूप से प्रदर्शित करते हुए अभिव्यक्त सभी विचारों और अभिव्यक्त विचारों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि द्वारा अभिलिखित किया जाएगा और प्रारंभिक भाषा में अंतर्यस्तुओं को स्पष्ट करते हुए कार्यवाहियों के अंत में श्रोताओं को पढ़ कर सुनाया जाएगा तथा करार पाए गए कार्यवृत्त पर उसी दिन जिला मजिस्ट्रेट या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को अंग्रेजित किया जाएगा।

6.5 जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों का एक विवरण और आवेदक की टीका-टिप्पणियों को भी स्थानीय भाषा में और अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाएगा तथा कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा।

6. लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को उस पचायत घर के कार्यालय पर जिसकी अधिकारिता में परियोजना अधिनियम 32 संबंधित जिला परिषद, जिला मजिस्ट्रेट और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के कार्यालय में सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति साधारण जासूसी के लिए अपने वेबसाइट पर कार्यवाहियों को प्रदर्शित भी करेगी। कार्यवाहियों पर टीका-टिप्पणियों को, यदि कोई हों, संबंधित विनियामक प्राधिकरणों और संबंधित आवेदक को प्रत्यक्षतः भेजी जा सकेगी।

7.0 लोक सुनवाई को पूरा करने के लिए कालावधि :

7.1 लोक सुनवाई आवेदक से अनुरोध पत्र की प्राप्ति की तारीख से पचास दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। अतः संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति लोक सुनवाई को पूरा होने के आठ दिनों के भीतर संबंधित विनियामक प्राधिकरण को लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को भेजेगी। आवेदक, लोक सुनवाई और लोक परामर्श के पश्चात् सेवार की गई अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट या प्रारूप पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट पर अनुसूचक रिपोर्ट की प्रति के साथ संबंधित विनियामक प्राधिकरण को, अनुसूचित लोक सुनवाई कार्यवाहियों की एक प्रति प्रत्यक्षतः भी अग्रेषित करेगा।

7.2 यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, नियत पचास दिनों के भीतर लोक सुनवाई करने में असफल रहती है तो केंद्रीय सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रवर्ग 'क' परियोजना या विद्युत्कल्याण के लिए और प्रवर्ग 'ख' परियोजना या किरायाकलाप के लिए और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, राज्य पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण के अनुरोध पर किसी अन्य अधिकरण या प्राधिकरण को इस अधिसूचना में अधिकृत प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नियोजित करेगी।

परिशिष्ट 5

(पृष्ठ 7 देखिए)

आंकलन के लिए विहित प्रक्रिया

1. आवेदक, संबंधित विनियामक प्राधिकरण को निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करते हुए, जहां लोक परामर्श आज्ञापक है, एक सादा सूचना के माध्यम से आवेदन करेगा :-

- अंतिम पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट की तीन हार्ड प्रतियां और एक सॉफ्ट प्रति
- लोक सुनवाई की कार्यवाहियों की वीडियो टेप की एक प्रति या सी.डी.
- अंतिम अभिव्यास योजना की दीप्त प्रतियां
- परियोजना साध्यता रिपोर्ट की एक प्रति



2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई अंतिम पर्यावरणीय समाघात-निर्धारण रिपोर्ट और अन्य सुसंगत दस्तावेजों को संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर कार्यालय में तत्परता से टीओआर के प्रतिनिर्देश से समीक्षा की जाएगी और ध्यान में रखी गई अपर्याप्तताओं को प्रत्येक अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करते हुए, जिसके अंतर्गत लोक सुनवाई कार्यवाहियां और प्राप्त की गई अन्य लोक प्रतिक्रियाएं भी हैं, प्रत्येक 1 या प्रत्येक 1क की एक प्रति और प्रस्तावों पर विचार करने के लिए पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति की बैठकों के लिए निश्चित तारीखें सहित पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति के सदस्यों को एकल सेट में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अल्पा संसूचित किया जाएगा।
3. जहां कोई लोक प्रदर्शन आकांक्षक नहीं है और इसलिए कोई औपचारिक पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन अपेक्षित नहीं है, जहां आंकलन, विहित आवेदन प्रत्येक 1 के आधार पर और अनुसूची की मद 8 से भिन्न सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में किसी पूर्व साध्यता रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। अनुसूची की मद 8 की दशा में, इसके विलक्षण परियोजना चक्र को ध्यान में रखते हुए, संबंधित पर्यावरणीय निर्धारण समिति या राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति, प्रत्येक 1, प्रत्येक 1क और धारणा योजना के आधार पर सभी प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आंकलन करेगी और पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए शर्तें नियत करेगी। जब कभी आवेदक सभी अन्य आवश्यक कानूनी अनुमोदनों सहित निश्चित पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों को पूरा करते हुए अनुमोदित स्कीम/भवन योजना प्रस्तुत करता है तो पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति, सक्षम प्राधिकारी को पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने की सिफारिश करेगी।
4. प्रत्येक आवेदन, पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति के समक्ष और इसका पूरा आंकलन, विहित शैति में अपेक्षित दस्तावेजों/ब्यौरो सहित इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर रखा जाएगा।
5. आवेदक को परियोजना प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति की निश्चित तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व सूचित किया जाएगा।
6. पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति की बैठक के कार्यवृत्त की बैठक के पांच कार्यकरण दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा और संबंधित विनियामक प्राधिकरण के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। परियोजना या क्रियाकलापों को पर्यावरणीय अनापत्ति को मंजूर किए जाने के लिए सिफारिश की दशा में, कार्यवृत्त में विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय सुझावों और शर्तों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा। यदि सिफारिशें नामंजूर करने के लिए हैं तो उसके कारणों को भी स्पष्ट रूप से कथित किया जाएगा।

## परिशिष्ट 6

(पृष्ठ 5 देखिए)

केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाने वाली प्रवर्ग 'क' परियोजनाओं के लिए सेक्टर/परियोजना विनिर्दिष्ट विशेषज्ञ आंकलन समिति और प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियों की संरचना

1. विशेषज्ञ आंकलन समितियाँ और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियाँ केवल निम्नलिखित पात्रता कसौटी को पूरा करने वाले वृत्तिकों और विशेषज्ञों से मिलकर बनेगी

वृत्तिक : ऐसा व्यक्ति जिसके पास कम से कम (i) एन.ए./एम.एस.सी डिग्री सहित संबंधित विद्या शाखा में पांच वर्ष का औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण या (ii) इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/वास्तुविद विद्या शाखाओं की दशा में, बी.टेक/बी.ई./बी.आर्क. डिग्री सहित क्षेत्र में विहित व्यावहारिक प्रशिक्षण सहित किसी वृत्तिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में चार वर्षीय औपचारिक प्रशिक्षण या (iii) अन्य वृत्तिक डिग्री (जैसे विधि) जिसमें पांच वर्ष का औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण या विहित व्यावहारिक प्रशिक्षण अंतर्बलित है, या (iv) विहित शिक्षता/कारीगारी तथा संबंधित वृत्तिक संगम द्वारा संचालित परिक्षाएं उत्तीर्ण की हो (जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी) या (v) किसी विश्वविद्यालय डिग्री के परचात किसी विश्वविद्यालय या सेवा अकादमी में दो वर्ष का औपचारिक प्रशिक्षण (जैसे एम.बी.ए./आई.ए.एस./आई.एफ.एस.) व्यक्ति वृत्तिकों का चयन करते समय उनके द्वारा उनके क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा।

विशेषज्ञ : ऊपर पात्रता कसौटी को पूरा करने वाला कोई वृत्तिक जिसके पास क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का सुसंगत अनुभव या संबंधित क्षेत्र में कोई उच्चतर डिग्री हो (जैसे पी.एच.डी. और कम से कम दस वर्ष का सुसंगत अनुभव)।

आयु : सत्तर वर्ष से नीचे। तथापि, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञों की अनुपलब्धता/कमी की दशा में विशेषज्ञ आंकलन समिति के सदस्यों की अधिकतम आयु को एकहतर वर्ष तक अनुज्ञात किया जा सकेगा।

2. पर्यावरणीय निर्धारण समिति के सदस्य निम्नलिखित क्षेत्रों/विद्या शाखाओं में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव वाले विशेषज्ञ होंगे। उस दशा में कि "विशेषज्ञ" की कसौटी को पूरा करने वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, तो उसी क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाले वृत्तिकों पर भी विचार किया जा सकेगा।

- पर्यावरण क्वालिटी विशेषज्ञ : पर्यावरणीय क्वालिटी के संबंध में माप/मानिटरिंग, विश्लेषण और निर्वचन में विशेषज्ञ।

- परियोजना प्रबंधन में क्षेत्रीय विशेषज्ञ : परियोजना प्रबंधन या सुसंगत क्षेत्रों में प्रक्रिया /प्रचालन/सुविधा प्रबंधन में विशेषज्ञ ।
  - पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्रक्रिया विशेषज्ञ : पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का संचालन और कार्यान्वयन तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना और अन्य प्रबंधन योजना तैयार करने में विशेषज्ञ और जो पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली मादी तकनीकों और औजारों में विस्तृत विशेषज्ञता और ज्ञान रखते हों ।
  - जोखिम निर्धारण विशेषज्ञ ।
  - पेड़ - पौधे और जीव- जन्तु प्रबंधन में प्राणी विज्ञान विशेषज्ञ ।
  - वन और वन्य जीव विशेषज्ञ ।
  - परियोजना आकलन में अनुभव सहित पर्यावरणीय अर्थशास्त्र विशेषज्ञ ।
3. पर्यावरणीय निर्धारण समिति की सदस्यता पंद्रह नियमित सदस्यों से अधिक की नहीं होगी । तथापि, अध्यक्ष समिति की किसी विशिष्ट बैठक के लिए किसी सुसंगत क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेंगे ।
4. अध्यक्ष, सुसंगत विकास क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित और पर्यावरणीय निति या प्रबंधन में अथवा लोक प्रशासन में अनुभव प्राप्त विशेषज्ञ होगा ।
5. अध्यक्ष, सदस्यों में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगा जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पर्यावरणीय निर्धारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।
6. पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि उसके सदस्य के रूप में समिति की सदस्यता करेगा ।
7. किसी सदस्य की अधिकतम पदावधि, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, प्रत्येक तीन वर्ष की दो पदावधि होगी ।
8. अध्यक्ष/सदस्य को किसी कारण और समुचित जांच के बिना पदावधि के अवसान से पूर्व नहीं हटाया जा सकेगा ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th September, 2006

S.O. 1533(E).—Whereas, a draft notification under Sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for imposing certain restrictions and prohibitions on new projects or activities, or on the expansion or modernization of existing projects or activities based on their potential environmental impacts as indicated in the Schedule to the notification, being undertaken in any part of India, unless prior environmental clearance has been accorded in accordance with the objectives of National Environment Policy as approved by the Union Cabinet on 18th May, 2006 and the procedure specified in the notification, by the Central Government or the State or Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), to be constituted by the Central Government in consultation with the State Government or the Union Territory Administration concerned under Sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 for the purpose of this notification, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1524(E), dated the 15th September, 2005 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public:

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 15<sup>th</sup> September, 2005:

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in supersession of the notification number S.O. 60 (E) dated the 27<sup>th</sup> January, 1994, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that on and from the date of its publication the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification entailing capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after the prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified hereinafter in this notification.

Includes the territorial waters

2. Requirements of prior Environmental Clearance (EC):- The following projects or activities shall require prior environmental clearance from the concerned regulatory authority, which shall hereinafter referred to be as the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for matters falling under Category 'A' in the Schedule and at State level the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) for matters falling under Category 'B' in the said Schedule, before any construction work, or preparation of land by the project management except for securing the land, is started on the project or activity:

- (i) All new projects or activities listed in the Schedule to this notification;
- (ii) Expansion and modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification with addition of capacity beyond the limits specified for the concerned sector, that is, projects or activities which cross the threshold limits given in the Schedule, after expansion or modernization;

(iii) Any change in product - mix in an existing manufacturing unit included in Schedule beyond the specified range.

3. State Level Environment Impact Assessment Authority:- (1) A State Level Environment Impact Assessment Authority hereinafter referred to as the SEIAA shall be constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of three Members including a Chairman and a Member - Secretary to be nominated by the State Government or the Union territory Administration concerned.

- (2) The Member-Secretary shall be a serving officer of the concerned State Government or Union territory administration familiar with environmental laws.
- (3) The other two Members shall be either a professional or expert fulfilling the eligibility criteria given in Appendix VI to this notification.
- (4) One of the specified Members in sub-paragraph (3) above who is an expert in the Environmental Impact Assessment process shall be the Chairman of the SEIAA.
- (5) The State Government or Union territory Administration shall forward the names of the Members and the Chairman referred in sub-paragraph 3 to 4 above to the Central Government and the Central Government shall constitute the SEIAA as an authority for the purposes of this notification within thirty days of the date of receipt of the names.
- (6) The non-official Member and the Chairman shall have a fixed term of three years (from the date of the publication of the notification by the Central Government constituting the authority).
- (7) All decisions of the SEIAA shall be unanimous and taken in a meeting.

4. Categorization of projects and activities:-

(i) All projects and activities are broadly categorized in to two categories - Category A and Category B, based on the spatial extent of potential impacts and potential impacts on human health and natural and man made resources.

(ii) All projects or activities included as Category 'A' in the Schedule, including expansion and modernization of existing projects or activities and change in product mix, shall require prior environmental clearance from the Central Government in the Ministry of Environment and Forests (MoEF) on the recommendations of an Expert Appraisal Committee (EAC) to be constituted by the Central Government for the purposes of this notification:

(iii) All projects or activities included as Category 'B' in the Schedule, including expansion and modernization of existing projects or activities as specified in sub paragraph (ii) of paragraph 2, or change in product-mix as specified in sub paragraph (iii) of paragraph 2, but excluding those which fulfill the General Conditions (GC) stipulated in the Schedule, will require prior environmental clearance from the State/Union territory Environment Impact Assessment Authority (SEIAA). The SEIAA shall base its decision on the recommendations of a State or Union territory level Expert Appraisal Committee (SEAC) as to be constituted for in this notification. In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category 'B' project shall be treated as a Category 'A' project:

**5. Screening, Scoping and Appraisal Committees:-**

The same Expert Appraisal Committees (EACs) at the Central Government and SEACs (hereinafter referred to as the (EAC) and (SEAC) at the State or the Union territory level shall screen, scope and appraise projects or activities in Category 'A' and Category 'B' respectively. EAC and SEAC's shall meet at least once every month.

- (a) The composition of the EAC shall be as given in Appendix VI. The SEAC at the State or the Union territory level shall be constituted by the Central Government in consultation with the concerned State Government or the Union territory Administration with identical composition;
- (b) The Central Government may, with the prior concurrence of the concerned State Governments or the Union territory Administrations, constitute one SEAC for more than one State or Union territory for reasons of administrative convenience and cost;
- (c) The EAC and SEAC shall be reconstituted after every three years;
- (d) The authorised members of the EAC and SEAC, concerned, may inspect any site(s) connected with the project or activity in respect of which the prior environmental clearance is sought, for the purposes of screening or scoping or appraisal, with prior notice of at least seven days to the applicant, who shall provide necessary facilities for the inspection;
- (e) The EAC and SEAC's shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

**6. Application for Prior Environmental Clearance (EC):-**

An application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made in the prescribed Form 1 annexed herewith and Supplementary Form 1A, if applicable, as given in Appendix II, after the identification of prospective site(s) for the project and/or activities to which the application relates, before commencing any construction activity, or preparation of land, at the site by the applicant. The applicant shall furnish, along with the application, a copy of the pre-feasibility project report except that, in case of construction projects or activities (item 8 of the Schedule) in addition to Form 1 and the Supplementary Form 1A, a copy of the conceptual plan shall be provided, instead of the pre-feasibility report.

**7. Stages in the Prior Environmental Clearance (EC) Process for New Projects:-**

7(1) The environmental clearance process for new projects will comprise of a maximum of four stages, all of which may not apply to particular cases as set forth below in this notification. These four stages in sequential order are:-

- Stage (1) Screening (Only for Category 'B' projects and activities)
- Stage (2) Scoping
- Stage (3) Public Consultation
- Stage (4) Appraisal

**1. Stage (1) - Screening:**

In case of Category 'B' projects or activities, this stage will entail the scrutiny of an application seeking prior environmental clearance made in Form 1 by the concerned State level Expert Appraisal Committee (SEAC) for determining whether or not the project or activity

requires further environmental studies for preparation of an Environmental Impact Assessment (EIA) for its appraisal prior to the grant of environmental clearance depending up on the nature and location specificity of the project. The projects requiring an Environmental Impact Assessment report shall be termed Category 'B1' and remaining projects shall be termed Category 'B2' and will not require an Environment Impact Assessment report. For categorization of projects into B1 or B2 except item 8 (b), the Ministry of Environment and Forests shall issue appropriate guidelines from time to time.

### II. Stage (2) - Scoping:

(i) "Scoping" refers to the process by which the Expert Appraisal Committee in the case of Category 'A' projects or activities, and State level Expert Appraisal Committee in the case of Category 'B1' projects or activities, including applications for expansion and/or modernization and/or change in product mix of existing projects or activities, determine detailed and comprehensive Terms Of Reference (TOR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environment Impact Assessment (EIA) Report in respect of the project or activity for which prior environmental clearance is sought. The Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned shall determine the Terms of Reference on the basis of the information furnished in the prescribed application Form I/Form 1A including Terms of Reference proposed by the applicant, a site visit by a sub-group of Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned only if considered necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, Terms of Reference suggested by the applicant if furnished and other information that may be available with the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. All projects and activities listed as Category 'B' in item 8 of the Schedule (Construction/Township/Commercial Complexes/Housing) shall not require Scoping and will be appraised on the basis of Form I/ Form 1A and the conceptual plan.

(ii) The Terms of Reference (TOR) shall be conveyed to the applicant by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as concerned within sixty days of the receipt of Form I. In the case of Category A Hydroelectric projects item 1(c) (i) of the Schedule the Terms of Reference shall be conveyed along with the clearance for pre-construction activities. If the Terms of Reference are not finalized and conveyed to the applicant within sixty days of the receipt of Form I, the Terms of Reference suggested by the applicant shall be deemed as the final Terms of Reference approved for the EIA studies. The approved Terms of Reference shall be displayed on the website of the Ministry of Environment and Forests and the concerned State Level Environment Impact Assessment Authority.

(iii) Applications for prior environmental clearance may be rejected by the regulatory authority concerned on the recommendation of the EAC or SEAC concerned at this stage itself. In case of such rejection, the decision together with reasons for the same shall be communicated to the applicant in writing within sixty days of the receipt of the application.

### III. Stage (3) - Public Consultation:

(i) "Public Consultation" refers to the process by which the concerns of local affected persons and others who have plausible stake in the environmental impacts of the project or activity are ascertained, with a view to taking into account all the material concerns in the project or activity design as appropriate. All Category 'A' and Category B1 projects or activities shall undertake Public Consultation, except the following:-

- (a) modernization of irrigation projects (item 1(c) (ii) of the Schedule).

- 40
- (b) all projects or activities located within industrial estates or parks (item 7(c) of the Schedule) approved by the concerned authorities, and which are not disallowed in such approvals.
  - (c) expansion of Roads and Highways (item 7 (f) of the Schedule) which do not involve any further acquisition of land.
  - (d) all Building /Construction projects/Area Development projects and Townships (item 8).
  - (e) all Category 'B2' projects and activities.
  - (f) all projects or activities concerning national defence and security or involving other strategic considerations as determined by the Central Government.

(ii) The Public Consultation shall ordinarily have two components comprising of:-

(a) a public hearing at the site or in its close proximity- district wise, to be carried out in the manner prescribed in Appendix IV, for ascertaining concerns of local affected persons;

(b) obtain responses in writing from other concerned persons having a plausible stake in the environmental aspects of the project or activity.

(iii) the public hearing at, or in close proximity to, the site(s) in all cases shall be conducted by the State Pollution Control Board (SPCB) or the Union territory Pollution Control Committee (UTPCC) concerned in the specified manner and forward the proceedings to the regulatory authority concerned within 45 (forty five ) of a request to the effect from the applicant.

(iv) in case the State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee concerned does not undertake and complete the public hearing within the specified period, and/or does not convey the proceedings of the public hearing within the prescribed period directly to the regulatory authority concerned as above, the regulatory authority shall engage another public agency or authority which is not subordinate to the regulatory authority, to complete the process within a further period of forty five days..

(v) If the public agency or authority nominated under the sub paragraph (iii) above reports to the regulatory authority concerned that owing to the local situation, it is not possible to conduct the public hearing in a manner which will enable the views of the concerned local persons to be freely expressed, it shall report the facts in detail to the concerned regulatory authority, which may, after due consideration of the report and other reliable information that it may have, decide that the public consultation in the case need not include the public hearing.

(vi) For obtaining responses in writing from other concerned persons having a plausible stake in the environmental aspects of the project or activity, the concerned regulatory authority and the State Pollution Control Board (SPCB) or the Union territory Pollution Control Committee (UTPCC) shall invite responses from such concerned persons by placing on their website the Summary EIA report prepared in the format given in Appendix IIIA by the applicant along with a copy of the application in the prescribed form, within seven days of the receipt of a written request for arranging the public hearing. Confidential information including non-disclosable or legally privileged information involving Intellectual Property Right, source specified in the application shall not be placed on the web site. The regulatory authority concerned may also use,



other appropriate media for ensuring wide publicity about the project or activity. The regulatory authority shall, however, make available on a written request from any concerned person the Draft EIA report for inspection at a notified place during normal office hours till the date of the public hearing. All the responses received as part of this public consultation process shall be forwarded to the applicant through the quickest available means.

(vii) After completion of the public consultation, the applicant shall address all the material environmental concerns expressed during this process, and make appropriate changes in the draft EIA and EMP. The final EIA report, so prepared, shall be submitted by the applicant to the concerned regulatory authority for appraisal. The applicant may alternatively submit a supplementary report to draft EIA and EMP addressing all the concerns expressed during the public consultation.

#### IV. Stage (4) - Appraisal:

(i) Appraisal means the detailed scrutiny by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee of the application and other documents like the Final EIA report, outcome of the public consultations including public hearing proceedings, submitted by the applicant to the regulatory authority concerned for grant of environmental clearance. This appraisal shall be made by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned in a transparent manner in a proceeding to which the applicant shall be invited for furnishing necessary clarifications in person or through an authorized representative. On conclusion of this proceeding, the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall make categorical recommendations to the regulatory authority concerned either for grant of prior environmental clearance on stipulated terms and conditions, or rejection of the application for prior environmental clearance, together with reasons for the same.

(ii) The appraisal of all projects or activities which are not required to undergo public consultation, or submit an Environment Impact Assessment report, shall be carried out on the basis of the prescribed application Form I and Form IA as applicable, any other relevant validated information available and the site visit wherever the same is considered as necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned.

(iii) The appraisal of an application shall be completed by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within sixty days of the receipt of the final Environment Impact Assessment report and other documents or the receipt of Form I and Form IA, where public consultation is not necessary and the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee shall be placed before the competent authority for a final decision within the next fifteen days. The prescribed procedure for appraisal is given in Appendix V.

#### 7(ii). Prior Environmental Clearance (EC) process for Expansion or Modernization or Change of product mix in existing projects:

All applications seeking prior environmental clearance for expansion with increase in the production capacity beyond the capacity for which prior environmental clearance has been granted under this notification or with increase in either lease area or production capacity in the case of mining projects or for the modernization of an existing unit with increase in the total production capacity beyond the threshold limit prescribed in the Schedule to this notification through change in process and or technology or involving a change in the product mix shall be made in Form I and they shall be considered by the concerned Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee within sixty days, who will decide on the due diligence

necessary including preparation of EIA and public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

**8. Grant or Rejection of Prior Environmental Clearance (EC):**

- (i) The regulatory authority shall consider the recommendations of the EAC or SEAC concerned and convey its decision to the applicant within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned or in other words within one hundred and five days of the receipt of the final Environment Impact Assessment Report, and where Environment Impact Assessment is not required, within one hundred and five days of the receipt of the complete application with requisite documents, except as provided below.
- (ii) The regulatory authority shall normally accept the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. In cases where it disagrees with the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, the regulatory authority shall request reconsideration by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned while stating the reasons for the disagreement. An intimation of this decision shall be simultaneously conveyed to the applicant. The Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, in turn, shall consider the observations of the regulatory authority and furnish its views on the same within a further period of sixty days. The decision of the regulatory authority after considering the views of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be final and conveyed to the applicant by the regulatory authority concerned within the next thirty days.
- (iii) In the event that the decision of the regulatory authority is not communicated to the applicant within the period specified in sub-paragraphs (i) or (ii) above, as applicable, the applicant may proceed as if the environment clearance sought for has been granted or denied by the regulatory authority in terms of the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned.
- (iv) On expiry of the period specified for decision by the regulatory authority under paragraph (i) and (ii) above, as applicable, the decision of the regulatory authority, and the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be public documents.
- (v) Clearances from other regulatory bodies or authorities shall not be required prior to receipt of applications for prior environmental clearance of projects or activities, or screening, or scoping, or appraisal, or decision by the regulatory authority concerned, unless any of these is sequentially dependent on such clearance either due to a requirement of law, or for necessary technical reasons.
- (vi) Deliberate concealment, and/or submission of false or misleading information or data which is material to screening or scoping or appraisal or decision on the application shall make the application liable for rejection, and cancellation of prior environmental clearance granted on that basis. Rejection of an application or cancellation of a prior environmental clearance already granted, on such ground, shall be decided by the regulatory authority, after giving a personal hearing to the applicant, and following the principles of natural justice.

**9. Validity of Environmental Clearance (EC):**

The "Validity of Environmental Clearance" is meant the period from which a prior environmental clearance is granted by the regulatory authority, or may be presumed by the applicant to have been granted under sub paragraph (iv) of paragraph 7 above, to the start of production operations by the project or activity, or completion of all construction operations in case of construction projects (item 8 of the Schedule), to which the application for prior environmental clearance refers. The prior environmental clearance granted for a project or activity shall be valid for a period of ten years in the case of River Valley projects (item 1(c) of the Schedule), project life as estimated by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee subject to a maximum of thirty years for mining projects and five years in the case of all other projects and activities. However, in the case of Area Development projects and Townships (item 8(b)), the validity period shall be limited only to such activities as may be the responsibility of the applicant as a developer. This period of validity may be extended by the regulatory authority concerned by a maximum period of five years provided an application is made to the regulatory authority by the applicant within the validity period, together with an updated Form I, and Supplementary Form IA, for Construction projects or activities (item 8 of the Schedule). In this regard the regulatory authority may also consult the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as the case may be.

**10. Post Environmental Clearance Monitoring:**

(i) It shall be mandatory for the project management to submit half-yearly compliance reports in respect of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copies to the regulatory authority concerned, on 1<sup>st</sup> June and 1<sup>st</sup> December of each calendar year.

(ii) All such compliance reports submitted by the project management shall be public documents. Copies of the same shall be given to any person, on application to the concerned regulatory authority. The latest such compliance report shall also be displayed on the web site of the concerned regulatory authority.

**11. Transferability of Environmental Clearance (EC):**

A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases.

**12. Operation of EIA Notification, 1994, till disposal of pending cases:**

From the date of final publication of this notification the Environment Impact Assessment (EIA) notification number S.O.60 (E) dated 27<sup>th</sup> January, 1994 is hereby superseded, except in suppression of the things done or omitted to be done before such suppression, to the extent that in case of all or some types of applications made for prior environmental clearance and pending on the date of final publication, of this notification, the Central Government may relax any one or all provisions of this notification except the list of the projects or activities requiring prior environmental clearance in Schedule I, or continue operation of some or all provisions of the said notification, for a period not exceeding one year from the date of issue of this notification.

## SCHEDULE

(See paragraph 2 and 7)

## LIST OF PROJECTS OR ACTIVITIES REQUIRING PRIOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE

Project or Activity	Category with threshold limit		Conditions if any	
	A	B		
1	Mining, extraction of natural resources and power generation (for a specified production capacity)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I(a)	Mining of minerals	<p>≥ 50 ha. of mining lease area</p> <p>Asbestos mining irrespective of mining area</p>	<p>&lt; 50 ha</p> <p>≥ 5 ha. of mining lease area.</p>	<p>General Condition shall apply</p> <p><u>Note</u></p> <p>Mineral prospecting (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey</p>
I(b)	Offshore and onshore oil and gas exploration, development & production	All projects		<p><u>Note</u></p> <p>Exploration Surveys (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey</p>
I(c)	River Valley projects	<p>(i) ≥ 50 MW hydroelectric power generation;</p> <p>(ii) ≥ 10,000 ha. of culturable command area</p>	<p>(i) &lt; 50 MW ≥ 25 MW hydroelectric power generation;</p> <p>(ii) &lt; 10,000 ha. of culturable command area</p>	General Condition shall apply
II(d)	Thermal Plants	<p>≥ 500 MW (coal/lignite/naphtha &amp; gas based);</p> <p>≥ 50 MW (Pet coke diesel and all other fuels -)</p>	<p>&lt; 500 MW (coal/lignite/naphtha &amp; gas based);</p> <p>&lt; 50 MW</p> <p>≥ 5 MW (Pet coke diesel and all other fuels )</p>	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1(e)	Nuclear power projects and processing of nuclear fuel	All projects		
2	Primary Processing			
2(a)	Coal washeries	$\geq 1$ million ton/annum throughput of coal	$< 1$ million ton/annum throughput of coal	General Condition shall apply (If located within mining area the proposal shall be appraised together with the mining proposal)
2(b)	Mineral beneficiation	$\geq 0.1$ million ton/annum mineral throughput	$< 0.1$ million ton/annum mineral throughput	General Condition shall apply (Mining proposal with Mineral beneficiation shall be appraised together for grant of clearance)

3 Materials Production				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3(a)	Metallurgical industries (ferrous & non ferrous)	<p>Primary metallurgical industry</p> <p>All projects</p> <p>bi Sponge iron manufacturing &gt; 200 TPD</p> <p>ci Secondary metallurgical processing industry</p> <p>All toxic and heavy metal producing units &gt; 20,000 tonnes annum</p>	<p>Sponge iron manufacturing &gt; 200 TPD</p> <p>Secondary metallurgical processing industry</p> <p>i All toxic and heavy metal producing units &gt; 20,000 tonnes annum</p> <p>ii All other non-toxic secondary metallurgical processing units &gt; 5000 tonnes annum</p>	<p>General Condition shall apply for Sponge iron manufacturing</p>
3(b)	Cement plants	<p>&gt; 1.0 million tonnes/annum production capacity</p>	<p>&gt; 1.0 million tonnes/annum production capacity. All Stand alone grinding units</p>	<p>General Condition shall apply</p>

Materials Processing				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4(a)	Petroleum refining industry	All projects		
4(b)	Coke oven plants	≥2,50,000 tonnes/annum	<2,50,000 & ≥25,000 tonnes/annum	
4(c)	Asbestos milling and asbestos based products	All projects		
4(d)	Chlor-alkali industry	≥300 TPD production capacity of a unit located outside the notified industrial area/estate	<300 TPD production capacity and located within a notified industrial area/estate	Specific Condition shall apply No new Mercury Cell based plants will be permitted and existing units converting to membrane cell technology are exempted from this Notification
4(e)	Soda ash industry	All projects		
4(f)	Leather/skin/hide processing industry	New projects outside the industrial area or expansion of existing units outside the industrial area	All new or expansion of projects located within a notified industrial area/estate	Specific condition shall apply
<b>5</b>				
Manufacturing/Fabrication				
5(a)	Chemical fertilizers	All projects		
5(b)	Pesticides industry and pesticide specific intermediates (excluding formulations)	All units producing technical grade pesticides		

48

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5(c)	Petro-chemical complexes (industries based on processing of petroleum fractions & natural gas and/or reforming to aromatics)	All projects		
5(d)	Manmade fibres manufacturing	Rayon	Others	General Condition shall apply
5(e)	Petrochemical based processing (processes other than cracking & reformation and not covered under the complexes)	Located out side the notified industrial area/ estate	Located in a notified industrial area/ estate	Specific Condition shall apply
5(f)	Synthetic organic chemicals industry (dyes & dye intermediates; bulk drugs and intermediates excluding drug formulations; synthetic rubbers; basic organic chemicals, other synthetic organic chemicals and chemical intermediates)	Located out side the notified industrial area/ estate	Located in a notified industrial area/ estate	Specific Condition shall apply
5(g)	Distilleries	(i) All Molasses based distilleries. (ii) All Cane juice non-molasses based distilleries ≥30 KLD	All Cane juice/non-molasses based distilleries <30 KLD	General Condition shall apply
5(h)	Integrated paint industry		All projects	General Condition shall apply



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5(i)	Pulp & paper industry excluding manufacturing of paper from waste paper and manufacture of paper from ready pulp with out bleaching	Pulp manufacturing and Paper manufacturing industry	Paper manufacturing industry without pulp manufacturing	General Condition shall apply
5(j)	Sugar Industry.		≥ 5000 tcd cane crushing capacity	General Condition shall apply
5(k)	Induction/arc furnaces/cupola furnaces STPH or more		All projects	General Condition shall apply
6		Service Sectors		
6(a)	Oil & gas transportation pipeline (crude and refinery/ petrochemical products), passing through national parks /sanctuaries/coral reefs /ecologically sensitive areas including LNG Terminal	All projects		

50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6(b)	Isolated storage & handling of hazardous chemicals (As per threshold planning quantity indicated in column 3 of schedule 2 & 3 of MSJHC Rules 1989 amended 2000)		All projects	General Condition shall apply
7		Physical Infrastructure including Environmental Services		
7(a)	Air ports	All projects		
7(b)	All ship breaking yards including ship breaking units	All projects		
7(c)	Industrial estates/ parks/ complexes/ areas, export processing Zones (EPZs), Special Economic Zones (SEZs), Biotech Parks, Leather Complexes.	If at least one industry in the proposed industrial estate falls under the Category A, entire industrial area shall be treated as Category A, irrespective of the area.  Industrial estates with area greater than 500 ha. and housing at least one Category B industry.	Industrial estates housing at least one Category B industry and area <500 ha.  Industrial estates of area > 500 ha. and not housing any industry belonging to Category A or B.	Special condition shall apply  Note: Industrial Estate of area below 500 ha. and not housing any industry of category A or B does not require clearance.
7(d)	Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs).	All integrated facilities having incineration & landfill or incineration alone	All facilities having land fill only	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7(e)	Ports, Harbours	≥ 5 million TPA of cargo handling capacity (excluding fishing harbours)	< 5 million TPA of cargo handling capacity and/or ports/ harbours ≥10,000 TPA of fish handling capacity	General Condition shall apply
7(f)	Highways	i) New National High ways; and ii) Expansion of National High ways greater than 30 KM, involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition, and passing through more than one State.	i) New State High ways; and ii) Expansion of National / State Highways greater than 30 km involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition.	General Condition shall apply
7(g)	Aerial ropeways		All projects	General Condition shall apply
7(h)	Common Effluent Treatment Plants (CETPs)		All projects	General Condition shall apply
7(i)	Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF)		All projects	General Condition shall apply

52

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8		Building / Construction projects/Area Development projects and Townships		
8(a)	Building and Construction projects		≥20000 sq.mtrs and <1,50,000 sq.mtrs. of built-up area*	#(built up area for covered construction; in the case of facilities open to the sky, it will be the activity area)
8(b)	Townships and Area Development projects.		Covering an area ≥ 50 ha and or built up area ≥1,50,000 sq .mtrs ++	**All projects under item 8(b) shall be appraised as Category B1

Note:-

**General Condition (GC):**

Any project or activity specified in Category 'B' will be treated as Category A, if located in whole or in part within 10 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972, (ii) Critically Polluted areas, as notified by the Central Pollution Control Board from time to time, (iii) Notified Eco-sensitive areas, (iv) Inter-State boundaries and international boundaries.

**Specific Condition (SC):**

If any Industrial Estate/Complex / Export processing Zones /Special Economic Zones/Biotech Parks / Leather Complex with homogeneous type of industries such as Items 4(d), 4(f), 5(e), 5(f), or those Industrial estates with pre -defined set of activities (not necessarily homogeneous, obtains prior environmental clearance, individual industries including proposed industrial housing within such estates /complexes will not be required to take prior environmental clearance, so long as the Terms and Conditions for the industrial estate/complex are complied with (Such estates/complexes must have a clearly identified management with the legal responsibility of ensuring adherence to the Terms and Conditions of prior environmental clearance, who may be held responsible for violation of the same throughout the life of the complex/estate).

[No. J-11013/56/2004-LA-II(I)]  
R. CHANDRAMOHAN, Jr. Secy.

APPENDIX I

(See paragraph - 6)

FORM I

(I) Basic Information

Name of the Project:

Location / site alternatives under consideration:

Size of the Project: \*

Expected cost of the project:

Contact Information:

Screening Category:

- Capacity corresponding to sectoral activity (such as production capacity for manufacturing, mining lease area and production capacity for mineral production, area for mineral exploration, length for linear transport infrastructure, generation capacity for power generation etc.)

## (II) Activity

- Construction, operation or decommissioning of the Project involving actions, which will cause physical changes in the locality (topography, land use, changes in water bodies, etc.)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data
1.1	Permanent or temporary change in land use, land cover or topography including increase in intensity of land use (with respect to local land use plan)		
1.2	Clearance of existing land, vegetation and buildings?		
1.3	Creation of new land uses?		
1.4	Pre-construction investigations e.g. bore holes, soil testing?		
1.5	Construction works?		
1.6	Demolition works?		
1.7	Temporary sites used for construction works or housing of construction workers?		
1.8	Above ground buildings, structures or earthworks including linear structures, cut and fill or excavations		
1.9	Underground works including mining or tunneling?		
1.10	Reclamation works?		
1.11	Dredging?		
1.12	Offshore structures?		
1.13	Production and manufacturing processes?		

54

1.14	Facilities for storage of goods or materials?
1.15	Facilities for treatment or disposal of solid waste or liquid effluents?
1.16	Facilities for long term housing of operational workers?
1.17	New road, rail or sea traffic during construction or operation?
1.18	New road, rail, air waterborne or other transport infrastructure including new or altered routes and stations, ports, airports etc?
1.19	Closure or diversion of existing transport routes or infrastructure leading to changes in traffic movements?
1.20	New or diverted transmission lines or pipelines?
1.21	Impoundment, damming, culverting, realignment or other changes to the hydrology of water courses or aquifers?
1.22	Stream crossings?
1.23	Abstraction or transfers of water from ground or surface waters?
1.24	Changes in water bodies or the land surface affecting drainage or run-off?
1.25	Transport of personnel or materials for construction, operation or decommissioning?
1.26	Long-term dismantling or decommissioning or restoration works?
1.27	Ongoing activity during decommissioning which could have an impact on the environment?
1.28	Influx of people to an area in either temporarily or permanently?
1.29	Introduction of alien species?
1.30	Loss of native species or genetic diversity?
1.31	Any other actions?

2. Use of Natural resources for construction or operation of the Project (such as land, water, materials or energy, especially any resources which are non-renewable or in short supply):

S.No.	Information/checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities /rates wherever possible) with source of information data
2.1	Land especially undeveloped or agricultural land (ha)		

2.2	Water (expected source & competing users) unit: KLD		
2.3	Minerals (MT)		
2.4	Construction material - stone, aggregates, and / soil (expected source - MT)		
2.5	Forests and timber (source - MT)		
2.6	Energy including electricity and fuels (source, competing users) Unit: fuel (MT), energy (MW)		
2.7	Any other natural resources (use appropriate standard units)		

3. Use, storage, transport, handling or production of substances or materials, which could be harmful to human health or the environment or raise concerns about actual or perceived risks to human health.

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
3.1	Use of substances or materials, which are hazardous (as per MSFHC rules) to human health or the environment (flora, fauna, and water supplies)		
3.2	Changes in occurrence of disease or affect disease vectors (e.g. insect or water borne diseases)		
3.3	Affect the welfare of people e.g. by changing living conditions?		
3.4	Vulnerable groups of people who could be affected by the project e.g. hospital patients, children, the elderly etc.,		
3.5	Any other causes		

4. Production of solid wastes during construction or operation or decommissioning (MT/month)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
4.1	Spoil, overburden or mine wastes		

156

4.2	Municipal waste (domestic and or commercial wastes)		
4.3	Hazardous wastes (as per Hazardous Waste Management Rules)		
4.4	Other industrial process wastes		
4.5	Surplus product		
4.6	Sewage sludge or other sludge from effluent treatment		
4.7	Construction or demolition wastes		
4.8	Redundant machinery or equipment		
4.9	Contaminated soils or other materials		
4.10	Agricultural wastes		
4.11	Other solid wastes		

5. Release of pollutants or any hazardous, toxic or noxious substances to air (Kg/hr)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
5.1	Emissions from combustion of fossil fuels from stationary or mobile sources		
5.2	Emissions from production processes		
5.3	Emissions from materials handling including storage or transport		
5.4	Emissions from construction activities including plant and equipment		
5.5	Dust or odours from handling of materials including construction materials, sewage and waste		



5.6	Emissions from incineration of waste		
5.7	Emissions from burning of waste in open air (e.g. slash materials, construction debris)		
5.8	Emissions from any other sources		

6. Generation of Noise and Vibration, and Emissions of Light and Heat:

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data with source of information data
6.1	From operation of equipment e.g. engines, ventilation plant, crushers		
6.2	From industrial or similar processes		
6.3	From construction or demolition		
6.4	From blasting or piling		
6.5	From construction or operational traffic		
6.6	From lighting or cooling systems		
6.7	From any other sources		

58

7. Risks of contamination of land or water from releases of pollutants into the ground or into sewers, surface waters, groundwater, coastal waters or the sea:

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
7.1	From handling, storage, use or spillage of hazardous materials		
7.2	From discharge of sewage or other effluents to water or the land (expected mode and place of discharge)		
7.3	By deposition of pollutants emitted to air into the land or into water		
7.4	From any other sources		
7.5	Is there a risk of long term build up of pollutants in the environment from these sources?		

8. Risk of accidents during construction or operation of the Project, which could affect human health or the environment

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
8.1	From explosions, spillages, fires etc from storage, handling, use or production of hazardous substances		
8.2	From any other causes		
8.3	Could the project be affected by natural disasters causing environmental damage (e.g. floods, earthquakes, landslides, cloudburst etc)?		



9. Factors which should be considered (such as consequential development) which could lead to environmental effects or the potential for cumulative impacts with other existing or planned activities in the locality

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
9.1	<p>Lead to development of supporting facilities, ancillary development or development stimulated by the project which could have impact on the environment e.g.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporting infrastructure (roads, power supply, waste or waste water treatment, etc.)</li> <li>• housing development</li> <li>• extractive industries</li> <li>• supply industries</li> <li>• other</li> </ul>		
9.2	Lead to after-use of the site, which could have an impact on the environment		
9.3	Set a precedent for later developments		
9.4	Have cumulative effects due to proximity to other existing or planned projects with similar effects		

(III) Environmental Sensitivity

S.No.	Areas	Name/ Identity	Aerial distance (within 15 km.) Proposed project location boundary
1	Areas protected under international conventions, national or local legislation for their ecological, landscape, cultural or other related value		

60

2	Areas which are important or sensitive for ecological reasons - Wetlands, watercourses or other water bodies, coastal zone, biospheres, mountains, forests		
3	Areas used by protected, important or sensitive species of flora or fauna for breeding, nesting, foraging, resting, over wintering, migration		
4	Inland, coastal, marine or underground waters		
5	State, National boundaries		
6	Routes or facilities used by the public for access to recreation or other tourist, pilgrim areas		
7	Defence installations		
8	Densely populated or built-up area		
9	Areas occupied by sensitive man-made land uses (hospitals, schools, places of worship, community facilities)		
10	Areas containing important, high quality or scarce resources (ground water resources, surface resources, forestry, agriculture, fisheries, tourism, minerals)		
11	Areas already subjected to pollution or environmental damage, (those where existing legal environmental standards are exceeded)		
12	Areas susceptible to natural hazard which could cause the project to present environmental problems (earthquakes, subsidence, landslide, erosion, flooding or extreme or adverse climatic conditions)		

(A). Proposed Terms of Reference for EIA studies

## APPENDIX II

(See paragraph 6)

FORM-1 A (only for construction projects listed under item 8 of the Schedule)

## CHECK LIST OF ENVIRONMENTAL IMPACTS

(Project proponents are required to provide full information and wherever necessary attach explanatory notes with the Form and submit along with proposed environmental management plan & monitoring programme)

## 1. LAND ENVIRONMENT

(Attach panoramic view of the project site and the vicinity)

- 1.1. Will the existing landuse get significantly altered from the project that is not consistent with the surroundings? (Proposed landuse must conform to the approved Master Plan - Development Plan of the area. Change of landuse if any and the statutory approval from the competent authority be submitted). Attach Maps of (i) site location, (ii) surrounding features of the proposed site (within 500 meters) and (iii) the site (indicating levels & contours) to appropriate scales. If not available attach only conceptual plans.
- 1.2. List out all the major project requirements in terms of the land area, built up area, water consumption, power requirement, connectivity, community facilities, parking needs etc.
- 1.3. What are the likely impacts of the proposed activity on the existing facilities adjacent to the proposed site? (Such as open spaces, community facilities, details of the existing landuse, disturbance to the local ecology).
- 1.4. Will there be any significant land disturbance resulting in erosion, subsidence & instability? (Details of soil type, slope analysis, vulnerability to subsidence, seismicity etc may be given).
- 1.5. Will the proposal involve alteration of natural drainage systems? (Give details on a contour map showing the natural drainage near the proposed project site)
- 1.6. What are the quantities of earthwork involved in the construction activity-cutting, filling, reclamation etc. (Give details of the quantities of earthwork involved, transport of fill materials from outside the site etc.)
- 1.7. Give details regarding water supply, waste handling etc during the construction period.
- 1.8. Will the low lying areas & wetlands get altered? (Provide details of how low lying and wetlands are getting modified from the proposed activity)
- 1.9. Whether construction debris & waste during construction cause health hazard? (Give quantities of various types of wastes generated during construction including the construction labour and the means of disposal)

## 2. WATER ENVIRONMENT

- 2.1. Give the total quantity of water requirement for the proposed project with the breakup of requirements for various uses. How will the water requirement met? State the sources & quantities and furnish a water balance statement.

62

- 2.2. What is the capacity (dependable flow or yield) of the proposed source of water?
- 2.3. What is the quality (of water required, in case, the supply is not from a municipal source? (Provide physical, chemical, biological characteristics with class of water quality)
- 2.4. How much of the water requirement can be met from the recycling of treated wastewater? (Give the details of quantities, sources and usage)
- 2.5. Will there be diversion of water from other users? (Please assess the impacts of the project on other existing uses and quantities of consumption)
- 2.6. What is the incremental pollution load from wastewater generated from the proposed activity? (Give details of the quantities and composition of wastewater generated from the proposed activity)
- 2.7. Give details of the water requirements met from water harvesting? Furnish details of the facilities created.
- 2.8. What would be the impact of the land use changes occurring due to the proposed project on the runoff characteristics (quantitative as well as qualitative) of the area in the post construction phase on a long term basis? Would it aggravate the problems of flooding or water logging in any way?
- 2.9. What are the impacts of the proposal on the ground water? (Will there be tapping of ground water; give the details of ground water table, recharging capacity, and approvals obtained from competent authority, if any)
- 2.10. What precautions/measures are taken to prevent the run-off from construction activities polluting land & aquifers? (Give details of quantities and the measures taken to avoid the adverse impacts)
- 2.11. How is the storm water from within the site managed? (State the provisions made to avoid flooding of the area, details of the drainage facilities provided along with a site layout indication contour levels)
- 2.12. Will the deployment of construction labourers particularly in the peak period lead to unsanitary conditions around the project site (Justify with proper explanation)
- 2.13. What on-site facilities are provided for the collection, treatment & safe disposal of sewage? (Give details of the quantities of wastewater generated, treatment capacities with technology & facilities for recycling and disposal)
- 2.14. Give details of dual plumbing system if treated waste used is used for flushing of toilets or any other use.

### 3. VEGETATION

- 3.1. Is there any threat of the project to the biodiversity? (Give a description of the local ecosystem with its unique features, if any)

3.2. Will the construction involve extensive clearing or modification of vegetation? (Provide a detailed account of the trees & vegetation affected by the project)

3.3. What are the measures proposed to be taken to minimize the likely impacts on important site features (Give details of proposal for tree plantation, landscaping, creation of water bodies etc along with a layout plan to an appropriate scale)

#### 4. FAUNA

4.1. Is there likely to be any displacement of fauna- both terrestrial and aquatic or creation of barriers for their movement? Provide the details.

4.2. Any direct or indirect impacts on the avifauna of the area? Provide details.

4.3. Prescribe measures such as corridors, fish ladders etc to mitigate adverse impacts on fauna

#### 5. AIR ENVIRONMENT

5.1. Will the project increase atmospheric concentration of gases & result in heat islands? (Give details of background air quality levels with predicted values based on dispersion models taking into account the increased traffic generation as a result of the proposed constructions)

5.2. What are the impacts on generation of dust, smoke, odorous fumes or other hazardous gases? Give details in relation to all the meteorological parameters.

5.3. Will the proposal create shortage of parking space for vehicles? Furnish details of the present level of transport infrastructure and measures proposed for improvement including the traffic management at the entry & exit to the project site.

5.4. Provide details of the movement patterns with internal roads, bicycle tracks, pedestrian pathways, footpaths etc., with areas under each category.

5.5. Will there be significant increase in traffic noise & vibrations? Give details of the sources and the measures proposed for mitigation of the above.

5.6. What will be the impact of DG sets & other equipment on noise levels & vibration in & ambient air quality around the project site? Provide details.

#### 6. AESTHETICS

6.1. Will the proposed constructions in any way result in the obstruction of a view, scenic amenity or landscapes? Are these considerations taken into account by the proponents?

6.2. Will there be any adverse impacts from new constructions on the existing structures? What are the considerations taken into account?

6.3. Whether there are any local considerations of urban form & urban design influencing the design criteria? They may be explicitly spelt out.

6.4. Are there any anthropological or archaeological sites or artefacts nearby? State if any other significant features in the vicinity of the proposed site have been considered.

#### 7. SOCIO-ECONOMIC ASPECTS

7.1. Will the proposal result in any changes to the demographic structure of local population? Provide the details.

- 7.2. Give details of the existing social infrastructure around the proposed project.
- 7.3. Will the project cause adverse effects on local communities, disturbance to sacred sites or other cultural values? What are the safeguards proposed?

### 8. BUILDING MATERIALS

- 8.1. May involve the use of building materials, with high-embodied energy. Are the construction materials produced with energy efficient processes? (Give details of energy conservation measures in the selection of building materials and their energy efficiency)
- 8.2. Transport and handling of materials during construction may result in pollution, noise & public nuisance. What measures are taken to minimize the impacts?
- 8.3. Are recycled materials used in roads and structures? State the extent of savings achieved?
- 8.4. Give details of the methods of collection, segregation & disposal of the garbage generated during the operation phases of the project.

### 9. ENERGY CONSERVATION

- 9.1. Give details of the power requirements, source of supply, backup source etc. What is the energy consumption assumed per square foot of built-up area? How have you tried to minimize energy consumption?
- 9.2. What type of, and capacity of, power back-up do you plan to provide?
- 9.3. What are the characteristics of the glass you plan to use? Provide specifications of its characteristics related to both short wave and long wave radiation?
- 9.4. What passive solar architectural features are being used in the building? Illustrate the applications made in the proposed project.
- 9.5. Does the layout of streets & buildings maximise the potential for solar energy devices? Have you considered the use of street lighting, emergency lighting and solar hot water systems for use in the building complex? Substantiate with details.
- 9.6. Is shading effectively used to reduce cooling/heating loads? What principles have been used to maximize the shading of Walls on the East and the West and the Roof? How much energy saving has been effected?
- 9.7. Do the structures use energy-efficient space conditioning, lighting and mechanical systems? Provide technical details. Provide details of the transformers and motor efficiencies, lighting intensity and air-conditioning load assumptions? Are you using CFC and HCFC free chillers? Provide specifications.
- 9.8. What are the likely effects of the building activity in altering the micro-climates? Provide a self assessment on the likely impacts of the proposed construction on creation of heat island & inversion effects?



9.9. What are the thermal characteristics of the building envelope? (a) roof; (b) external walls; and (c) fenestration? Give details of the material used and the U-values or the R values of the individual components.

9.10. What precautions & safety measures are proposed against fire hazards? Furnish details of emergency plans.

9.11. If you are using glass as wall material provides details and specifications including emissivity and thermal characteristics.

9.12. What is the rate of air infiltration into the building? Provide details of how you are mitigating the effects of infiltration.

9.13. To what extent the non-conventional energy technologies are utilised in the overall energy consumption? Provide details of the renewable energy technologies used.

#### 10. Environment Management Plan

The Environment Management Plan would consist of all mitigation measures for each item wise activity to be undertaken during the construction, operation and the entire life cycle to minimize adverse environmental impacts as a result of the activities of the project. It would also delineate the environmental monitoring plan for compliance of various environmental regulations. It will state the steps to be taken in case of emergency such as accidents at the site including fire.

#### APPENDIX III

(See paragraph 7)

#### GENERIC STRUCTURE OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESMENT DOCUMENT

S.NO	EIA STRUCTURE	CONTENTS
1.	Introduction	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Purpose of the report</li> <li>• Identification of project &amp; project proponent</li> <li>• Brief description of nature, size, location of the project and its importance in the country, region</li> <li>• Scope of the study – details of regulatory scoping carried out (As per Terms of Reference)</li> </ul>
2.	Project Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Condensed description of those aspects of the project (based on project feasibility study), likely to cause environmental effects. Details should be provided to give clear picture of the following:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Type of project</li> <li>• Need for the project</li> <li>• Location (maps showing general location, specific location, project boundary &amp; project site layout)</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Size or magnitude of operation (incl. Associated activities required by or for the project)</li> <li>• Proposed schedule for approval and implementation</li> <li>• Technology and process description</li> <li>• Project description. Including drawings showing project layout, components of project etc. Schematic representations of the feasibility drawings which give information important for EIA purpose</li> <li>• Description of mitigation measures incorporated into the project to meet environmental standards, environmental operating conditions, or other EIA requirements (as required by the scope)</li> <li>• Assessment of New &amp; untested technology for the risk of technological failure</li> </ul>
3.	Description of the Environment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Study area, period, components &amp; methodology</li> <li>• Establishment of baseline for valued environmental components, as identified in the scope</li> <li>• Base maps of all environmental components</li> </ul>
4.	Anticipated Environmental Impacts & Mitigation Measures	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project</li> <li>• Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified</li> <li>• Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components</li> <li>• Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance. Assigning significance)</li> <li>• Mitigation measures</li> </ul>
5.	Analysis of Alternatives (Technology & Site)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In case, the scoping exercise results in need for alternatives:</li> <li>• Description of each alternative</li> <li>• Summary of adverse impacts of each alternative</li> <li>• Mitigation measures proposed for each alternative and</li> <li>• Selection of alternative</li> </ul>

6.	Environmental Monitoring Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>Technical aspects of monitoring the effectiveness of mitigation measures (incl. Measurement methodologies, frequency, location, data analysis, reporting schedules, emergency procedures, detailed budget &amp; procurement schedules)</li> </ul>
7.	Additional Studies	<ul style="list-style-type: none"> <li>Public Consultation</li> <li>Risk assessment</li> <li>Social Impact Assessment, R&amp;R Action Plans</li> </ul>
8.	Project Benefits	<ul style="list-style-type: none"> <li>Improvements in the physical infrastructure</li> <li>Improvements in the social infrastructure</li> <li>Employment potential –skilled; semi-skilled and unskilled</li> <li>Other tangible benefits</li> </ul>
9.	Environmental Benefit Analysis	Cost If recommended, at the Scoping stage
10.	EMP	Description of the administrative aspects of ensuring that mitigative measures are implemented and their effectiveness monitored, after approval of the EIA
11.	Summary & Conclusion (This will constitute the summary of the EIA Report)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Overall justification for implementation of the project</li> <li>Explanation of how adverse effects have been mitigated</li> </ul>
12.	Disclosure of Consultants engaged	The names of the Consultants engaged with their brief resume and nature of Consultancy rendered

APPENDIX III A  
(See paragraph 7)

CONTENTS OF SUMMARY ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

The Summary EIA shall be a summary of the full EIA Report, condensed to ten A-4 size pages at the maximum. It should necessarily cover in brief the following Chapters of the full EIA Report:

1. Project Description
2. Description of the Environment
3. Anticipated Environmental impacts and mitigation measures
4. Environmental Monitoring Programme
5. Additional Studies
6. Project Benefits
7. Environment Management Plan

**APPENDIX IV**  
(See paragraph 7)

**PROCEDURE FOR CONDUCT OF PUBLIC HEARING**

1.0 The Public Hearing shall be arranged in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible public participation at the project site(s) or in its close proximity District-wise, by the concerned State Pollution Control Board (SPCB) or the Union Territory Pollution Control Committee (UTPCC).

2.0 The Process:

2.1 The Applicant shall make a request through a simple letter to the Member Secretary of the SPCB or Union Territory Pollution Control Committee, in whose jurisdiction the project is located, to arrange the public hearing within the prescribed statutory period. In case the project site is extending beyond a State or Union Territory, the public hearing is mandated in each State or Union Territory in which the project is sited and the Applicant shall make separate requests to each concerned SPCB or UTPCC for holding the public hearing as per this procedure.

2.2 The Applicant shall enclose with the letter of request, at least 10 hard copies and an equivalent number of soft (electronic) copies of the draft EIA Report with the generic structure given in Appendix III including the Summary Environment Impact Assessment report in English and in the local language, prepared strictly in accordance with the Terms of Reference communicated after Scoping (Stage-2). Simultaneously the applicant shall arrange to forward copies, one hard and one soft, of the above draft EIA Report along with the Summary EIA report to the Ministry of Environment and Forests and to the following authorities or offices, within whose jurisdiction the project will be located:

- (a) District Magistrate/s
- (b) Zila Parishad or Municipal Corporation
- (c) District Industries Office
- (d) Concerned Regional Office of the Ministry of Environment and Forests

2.3 On receiving the draft Environmental Impact Assessment report, the above-mentioned authorities except the MoEF, shall arrange to widely publicize it within their respective jurisdictions requesting the interested persons to send their comments to the concerned regulatory authorities. They shall also make available the draft EIA Report for inspection electronically or otherwise to the public during normal office hours till the Public Hearing is over. The Ministry of Environment and Forests shall promptly display the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report on its website, and also make the full draft EIA available for reference at a notified place during normal office hours in the Ministry at Delhi.

2.4 The SPCB or UTPCC concerned shall also make similar arrangements for giving publicity about the project within the State/Union Territory and make available the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report (Appendix III A) for inspection in select offices or public libraries or panchayats etc. They shall also additionally

make available a copy of the draft Environmental Impact Assessment report to the above five authorities/offices viz. Ministry of Environment and Forests, District Magistrate etc.

### 3.0 Notice of Public Hearing:

3.1 The Member-Secretary of the concerned SPCB or UTPCC shall finalize the date, time and exact venue for the conduct of public hearing within 7(seven) days of the date of receipt of the draft Environmental Impact Assessment report from the project proponent, and advertise the same in one major National Daily and one Regional vernacular Daily. A minimum notice period of 30(thirty) days shall be provided to the public for furnishing their responses:

3.2 The advertisement shall also inform the public about the places or offices where the public could access the draft Environmental Impact Assessment report and the Summary Environmental Impact Assessment report before the public hearing.

3.3 No postponement of the date, time, venue of the public hearing shall be undertaken, unless some unoward emergency situation occurs and only on the recommendation of the concerned District Magistrate the postponement shall be notified to the public through the same National and Regional vernacular dailies and also prominently displayed at all the identified offices by the concerned SPCB or Union Territory Pollution Control Committee.

3.4 In the above exceptional circumstances fresh date, time and venue for the public consultation shall be decided by the Member-Secretary of the concerned SPCB or UTPCC only in consultation with the District Magistrate and notified afresh as per procedure under 3.1 above.

### 4.0 The Panel

4.1 The District Magistrate or his or her representative not below the rank of an Additional District Magistrate, assisted by a representative of SPCB or UTPCC, shall supervise and preside over the entire public hearing process.

### 5.0 Videography

5.1 The SPCB or UTPCC shall arrange to video film the entire proceedings. A copy of the videotape or a CD shall be enclosed with the public hearing proceedings while forwarding it to the Regulatory Authority concerned.

### 6.0 Proceedings

6.1 The attendance of all those who are present at the venue shall be noted and annexed with the final proceedings.

6.2 There shall be no quorum required for attendance for starting the proceedings.

6.3 A representative of the applicant shall initiate the proceedings with a presentation on the project and the Summary EIA report.

6.4 Every person present at the venue shall be granted the opportunity to seek information or clarifications on the project from the Applicant. The summary of the public

hearing proceedings accurately reflecting all the views and concerns expressed shall be recorded by the representative of the SPCB or UTPCC and read over to the audience at the end of the proceedings explaining the contents in the vernacular language and the agreed minutes shall be signed by the District Magistrate or his or her representative on the same day and forwarded to the SPCB/UTPCC concerned.

6.5 A Statement of the issues raised by the public and the comments of the Applicant shall also be prepared in the local language and in English and annexed to the proceedings.

6.6 The proceedings of the public hearing shall be conspicuously displayed at the office of the Panchyats within whose jurisdiction the project is located, office of the concerned Zila Parishad, District Magistrate and the SPCB or UTPCC. The SPCB or UTPCC shall also display the proceedings on its website for general information. Comments, if any, on the proceedings which may be sent directly to the concerned regulatory authorities and the Applicant concerned.

7.0 Time period for completion of public hearing

7.1 The public hearing shall be completed within a period of 45 (forty five) days from date of receipt of the request letter from the Applicant. Therefore the SPCB or UTPCC concerned shall send the public hearing proceedings to the concerned regulatory authority within 8(eight) days of the completion of the public hearing. The applicant may also directly forward a copy of the approved public hearing proceedings to the regulatory authority concerned along with the final Environmental Impact Assessment report or supplementary report to the draft EIA report prepared after the public hearing and public consultations.

7.2 If the SPCB or UTPCC fails to hold the public hearing within the stipulated 45(forty five) days, the Central Government in Ministry of Environment and Forests for Category 'A' project or activity and the State Government or Union Territory Administration for Category 'B' project or activity at the request of the SEIAA, shall engage any other agency or authority to complete the process, as per procedure laid down in this notification.

#### APPENDIX -V (See paragraph 7)

#### PROCEDURE PRESCRIBED FOR APPRAISAL

1. The applicant shall apply to the concerned regulatory authority through a simple communication, enclosing the following documents where public consultations are mandatory:-

- Final Environment Impact Assessment Report (20(twenty) hard copies and 1 (one) soft copy)
- A copy of the video tape or CD of the public hearing proceedings
- A copy of final layout plan (20 copies)
- A copy of the project feasibility report (1 copy)

2. The Final EIA Report and the other relevant documents submitted by the applicant shall be scrutinized in office within 30 days from the date of its receipt by the concerned Regulatory Authority strictly with reference to the TOR and the inadequacies noted shall be communicated electronically or otherwise in a single set to the Members of the EAC

/SEAC enclosing a copy each of the Final EIA Report including the public hearing proceedings and other public responses received along with a copy of Form 1 or Form 1A and scheduled date of the EAC /SEAC meeting for considering the proposal.

3. Where a public consultation is not mandatory and therefore a formal EIA study is not required, the appraisal shall be made on the basis of the prescribed application Form 1 and a pre-feasibility report in the case of all projects and activities other than Item 8 of the Schedule. In the case of Item 8 of the Schedule, considering its unique project cycle, the EAC or SEAC concerned shall appraise all Category B projects or activities on the basis of Form 1, Form 1A and the conceptual plan and stipulate the conditions for environmental clearance. As and when the applicant submits the approved scheme/building plans complying with the stipulated environmental clearance conditions with all other necessary statutory approvals, the EAC /SEAC shall recommend the grant of environmental clearance to the competent authority.

4. Every application shall be placed before the EAC /SEAC and its appraisal completed within 60 days of its receipt with requisite documents / details in the prescribed manner.

5. The applicant shall be informed at least 15 (fifteen) days prior to the scheduled date of the EAC /SEAC meeting for considering the project proposal.

6. The minutes of the EAC /SEAC meeting shall be finalised within 5 working days of the meeting and displayed on the website of the concerned regulatory authority. In case the project or activity is recommended for grant of EC, then the minutes shall clearly list out the specific environmental safeguards and conditions. In case the recommendations are for rejection, the reasons for the same shall also be explicitly stated.

#### APPENDIX VI

(See paragraph 5)

#### COMPOSITION OF THE SECTOR/ PROJECT SPECIFIC EXPERT APPRAISAL COMMITTEE (EAC) FOR CATEGORY A PROJECTS AND THE STATE/UT LEVEL EXPERT APPRAISAL COMMITTEES (SEACs) FOR CATEGORY B PROJECTS TO BE CONSTITUTED BY THE CENTRAL GOVERNMENT

1. The Expert Appraisal Committees (EAC(s) and the State/UT Level Expert Appraisal Committees (SEACs) shall consist of only professionals and experts fulfilling the following eligibility criteria:

**Professional:** The person should have at least (i) 5 years of formal University training in the concerned discipline leading to a MA/MSc Degree, or (ii) in case of Engineering /Technology/Architecture disciplines, 4 years formal training in a professional training course together with prescribed practical training in the field leading to a B.Tech/B.E./B.Arch. Degree, or (iii) Other professional degree (e.g. Law) involving a total of 5 years of formal University training and prescribed practical training, or (iv) Prescribed apprenticeship/article ship and pass examinations conducted by the concerned professional association (e.g. Chartered Accountancy), or (v) a University degree, followed by 2 years of formal training in a University or Service Academy (e.g. MBA/IAS/IFS). In selecting the individual professionals, experience gained by them in their respective fields will be taken note of.

**Expert:** A professional fulfilling the above eligibility criteria with at least 15 years of relevant experience in the field, or with an advanced degree (e.g. Ph.D.) in a concerned field and at least 10 years of relevant experience.

**Age:** Below 70 years. However, in the event of the non-availability of paucity of experts in a given field, the maximum age of a member of the Expert Appraisal Committee may be allowed up to 75 years.

72

2. The Members of the EAC shall be Experts with the requisite expertise and experience in the following fields /disciplines. In the event that persons fulfilling the criteria of "Experts" are not available, Professionals in the same field with sufficient experience may be considered:

- **Environment Quality Experts:** Experts in measurement, monitoring, analysis and interpretation of data in relation to environmental quality
- **Sectoral Experts in Project Management:** Experts in Project Management or Management of Process/Operations/Facilities in the relevant sectors.
- **Environmental Impact Assessment Process Experts:** Experts in conducting and carrying out Environmental Impact Assessments (EIAs) and preparation of Environmental Management Plans (EMPs) and other Management plans and who have wide expertise and knowledge of predictive techniques and tools used in the EIA process
- **Risk Assessment Experts**
- **Life Science Experts** in floral and faunal management
- **Forestry and Wildlife Experts**
- **Environmental Economics Expert** with experience in project appraisal.

3. The Membership of the EAC shall not exceed 15 (fifteen) regular Members. However, the Chairperson may co-opt an expert as a Member in a relevant field for a particular meeting of the Committee.

4. The Chairperson shall be an outstanding and experienced environmental policy expert or expert in management or public administration with wide experience in the relevant development sector.

5. The Chairperson shall nominate one of the Members as the Vice Chairperson who shall preside over the EAC in the absence of the Chairman /Chairperson.

6. A representative of the Ministry of Environment and Forests shall assist the Committee as its Secretary.

7. The maximum tenure of a Member, including Chairperson, shall be for 2 (two) terms of 3 (three) years each.

8. The Chairman / Members may not be removed prior to expiry of the tenure without cause and proper enquiry.



①

No. K-13011/7/2009- DDIB  
Government of India  
Ministry of Urban Development  
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi  
Dated the 22<sup>nd</sup> October, 2009

MC  
338  
29/9/09

PC-Seq. Subject-  
Com(615)

Extraordinary Gazette Notification - for publication of  
Notification dated 20.10.2009 regarding Change of land  
use of an area measuring 9000 sqm. at Aliganj, Jorbagh  
from 'Residential' to 'Government Office'.

(Separate Copies)

455-G-Plan  
27/10/09  
26/10/09

A copy of Notification No.2632 (E) dated 20<sup>th</sup> October, 2009  
published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for  
information and necessary action.

संज्ञक संख्या  
संज्ञा सं. 23/2-B  
दिनांक 23/10/09

(P.K. Santra)  
Under Secretary  
Tel.No.23061681

Copy to:

- ✓ 1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi
2. Chairperson, NDMC, Palika Kendra, New Delhi
3. Commissioner (MCD), Town Hall, Delhi
4. Principal Secretary (UD), Govt. of National Capital Territory of  
Delhi, I.P.Estate, Delhi.
5. The Joint Director (MP), Delhi Development Authority, Vikas  
Sadan, New Delhi with reference to their No.F.20(4)2009-MP  
dated 13.10.2009.
6. L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.

Copy to:- NIC, Ministry of Urban Development with a request to put  
the above Notification on the website of this Ministry immediately.

To circulate to  
concerned officers - h  
DD(MC) 29/10

Office of the DD(MC)  
Copy to Com (Ply) for  
favour of information  
C (Ply) DD(MC) on a

29/10/09

DD(MC) 29/10/09  
M 2A

2



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1677]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 20, 2009/आश्विन 28, 1931

No. 1677]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 2009/ASVINA 28, 1931

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2009

का.आ. 2632(अ).—यतः नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1 जुलाई, 2009 की सं. का.आ. 1606(अ) की सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा-अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया गया है; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान-2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

अलीगंज (जोरबाग), नई दिल्ली, जोन डी में आने वाला 9000 वर्ग मीटर (7.2 है. शेष भूमि से अलग किया हुआ क्षेत्र) के माप वाले निम्न भू क्षेत्र का उपयोग नीचे दिए विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :-

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	भू-उपयोग परिवर्तित	सीमा
1	2	3	4	5
जोन 'डी' में अलीगंज (जोरबाग)	9000 वर्ग मीटर	आवासीय	सरकारी कार्यालय	पूर्व—एन डी एम सी, टाईप-1 क्वार्टर और एन डी एम सी सामुदायिक हॉल और 15 मी. मार्गाधिकार की प्रस्तावित सड़क (पी पी आर ए तक सम्पर्क सड़क) पश्चिम—डी डी ए फ्लैट्स, जोरबाग और बी के दत्त कॉलोनी और 12 मी. मार्गाधिकार सम्पर्क सड़क

उत्तर— 24 मी. मार्गाधिकार और लोधी कॉलोनी  
दक्षिण— अलीगंज की जी पी आर ए कालोनी (टाईप-IV  
स्पेशल, और टाईप-V के रूप में विकास हेतु  
निर्धारित मौजूदा टाईप-I क्वार्टर)

[सं. के-13011/7/2009-डीडीआईबी]

पी. के. सांत्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2009

S.O. 2632(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 1606(E), dated 1st July, 2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44, of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification

The land use of the following area measuring 9000 sq. m. (carved out of 7.2 ha. of land of remaining area) at Aliganj (Jorbagh), New Delhi falling in Zone-D is changed as per description listed below :—

Location	Area	Land Use (MPD-2021)	Land Use Changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Aliganj (Jorbagh) in Zone-D	9000 sq. m.	Residential	Government Office	East— NDMC, Type-I Quarters and NDMC Community Hall and proposed road of 15 mtrs. ROW (Approach road to GPRA) West— DDA Flats, Jorbagh and B.K. Dutt Colony and 12 mtrs. ROW approach road North— 24 mtrs. ROW and Lodhi Colony South— GPRA Colony of Aliganj (existing Type-I quarters scheduled for redevelopment as Type-IV Spl. and Type-V)

[No. K-13011/7/2009-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2201]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 26, 2009/पौष 5, 1931

No. 2201]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 26, 2009/PAUSA 5, 1931

दिल्ली विकास प्राधिकरण  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2009

का.आ. 3301(अ).— एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की धारा 5(2) (एच) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या के-11011/5/2009- डी डी आई ए दिनांक 16 दिसम्बर, 2009 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री जे. पी. अग्रवाल और श्री सईद शाहनवाज हुसैन, सांसद (लोक सभा), व डॉ. कर्ण सिंह, सांसद सदस्य, राज्य सभा (जिनका राज्य सभा सदस्य के रूप में कार्यकाल दिनांक 27-1-2012 तक है) को विधिवत रूप से प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में चुना गया है।

[सं. फा. 1(2)2009/एसी/एमसी/ दि.वि.प्रा./117]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY  
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2009

S.O. 3301(E).— It is hereby notified that under Section 5 (2) (h) of the Delhi Development Act, 1957, the Government of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/5/2009-DDIA dated 16th December, 2009 communicated that Lok Sabha Members of Parliament Shri J. P. Aggarwal and Shri Syed Shahnawaz Hussain and Rajya Sabha Member of Parliament, Dr. Karan Singh, (current term in Rajya Sabha up to 27-1-2012) have been elected to be members of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1(2)2009/AC/MC/DDA/117]

V. M. BANSAL, Principal Commr.-cum-Secy.

5

No.1/22/1/2010-Cab.  
GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)  
CABINET SECRETARIAT (MANTRIMANDAL SACHIVALAYA)  
RASHTRAPATI BHAVAN

117A/SLUD/2010  
D 4/03

New Delhi, the 23<sup>rd</sup> February, 2010

The undersigned is directed to circulate herewith for information a copy of the notification dated 22<sup>nd</sup> February, 2010 by the President under clause (3) of article 77 of the Constitution regarding Amendment to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961.

(K.L. Sharma)  
Director (Cabinet)  
Tele: 23015802

Series No. 296  
Dated: 22<sup>nd</sup> February, 2010

To

All Secretaries of the Government of India/Chairman, Railway Board/Director, Institute of Secretariat Training and Management/Establishment Officer, Department of Personnel and Training/Accounts Officer, Pay and Accounts Office, Cabinet Secretariat.

\*\*\*\*

Copy, with a copy of enclosure, forwarded to all Ministries/Departments of Government of India/Lok Sabha Secretariat (Question Branch/Lok Sabha Secretariat (Legislative Branch)/Rajya Sabha Secretariat (Question Branch/Committee Coordination Section)/Union Public Service Commission/Budget Division, Department of Economic Affairs/Parliamentary Library (5 Copies).

(K.L. Sharma)  
Director (Cabinet)

\*\*\*\*

Copy, with a copy of enclosure, forwarded to the Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Language Wing, Indian Law Building, Bhagwan Das Marg, New Delhi, for information.

(K.L. Sharma)  
Director (Cabinet)

100 copies.  
200

EA  
J.M.  
4/3  
D/CC  
Ranney  
3/3  
4/3/10  
US/50 (C)  
R/S  
on Secords  
Date  
to Sr. offm.  
in New Delhi

सं० 1/22/1/2010-मंत्रि०

भारत सरकार  
मंत्रिमंडल सचिवालय  
राष्ट्रपति भवन

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2010

संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) के अन्तर्गत भारत सरकार (कार्य आर्बंटन) नियम, 1961 में संशोधन संबंधी राष्ट्रपति की दिनांक 22 फरवरी, 2010 की अधिसूचना की एक प्रति सूचनार्थ इसके साथ परिचालित करने का मुझे निदेश हुआ है।

(के०एल० शर्मा)  
निदेशक (मंत्रिमंडल)  
दूरभाष: 23015802

अवलि सं० 296  
दिनांक: 22 फरवरी, 2010

सेवा में,

भारत सरकार के सभी सचिव/अध्यक्ष, रेल बोर्ड/ निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान/स्थापना अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/लेखा अधिकारी, वेतन एवं लेखा कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय।

प्रतिलिपि, संलग्नक की प्रति सहित, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/लोक सभा सचिवालय(प्रश्न शाखा)/ लोक सभा सचिवालय (विधायी शाखा)/राज्य सभा सचिवालय (प्रश्न शाखा)/समििति समन्वय अनुभाग/संघ लोक सेवा आयोग/बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग/संसद पुस्तकालय (3 प्रतियाँ) को प्रेषित।

(के०एल० शर्मा)  
निदेशक (मंत्रिमंडल)

प्रतिलिपि, संलग्नक की प्रति सहित, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता, राजभाषा खंड, भारतीय विधि भवन, भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

(के०एल० शर्मा)  
निदेशक (मंत्रिमंडल)

(To be published in  
Part II, Section 3,  
Sub - section (ii)  
of the Gazette of  
India, Extra Ordinary  
Dated the 23<sup>rd</sup> February, 2010)

Doc. CD- 144 /2010

RASHTRAPATI BHAVAN  
NEW DELHI

Notification

Dated the 22 February, 2010

S O. \_\_\_\_\_ (E).- In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business), Two Hundred and Ninety Sixth Amendment Rules, 2010.  
(2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the SECOND SCHEDULE,-
  - (i) under the heading "MINISTRY OF DEFENCE (RAKSHA MANTRALAYA)", under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION (RAKSHA UTPADAN VIBHAG)", after entry 14, the following entry shall be inserted, namely:-

"15. Hindustan Shipyard Limited.";
  - (ii) under the heading "MINISTRY OF SHIPPING (POT PARIVAHAN MANTRALAYA)", entry 31 shall be omitted:

- (iii) under the heading "MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SANKHYIKI AUR KARYAKRAM KARYANVAYAN MANTRALAYA)", for entry 19 the following entry shall be substituted, namely:-

**"19. Monitoring of projects of Rs. 150 crores and above.";**

- (iv) under the heading "PLANNING COMMISSION (YOJANA AYOG)", after entry 11 and the note thereunder, the following entry shall be inserted, namely:-

**"12. Unique Identification Authority of India (UIDAI) -**

- (a) Policy, planning and implementation of Unique Identification Number (UID) for residents in India and all matters related to it.  
(b) Unique Identification Authority of India (UIDAI) and connected matters."

Pratibha Devisingh Patil  
President

[File No.1/22/1/2010-Cab.]



(भारत के राजपत्र, असाधारण,  
भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (iii),  
तारीख 23 फरवरी, 2010 में  
प्रकाशनार्थ)

प्रलेख सीडी- 144/2010

राष्ट्रपति भवन  
नई दिल्ली

अधिसूचना

तारीख 22 फरवरी, 2010

का0आ0.....(अ).- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) दो सौ छियानवेवां संशोधन नियम, 2010 है।  
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में-
  - (i) "रक्षा मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "ख. रक्षा उत्पादन विभाग" उपशीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 14 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-  
"15. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड!";
  - (ii) "पोत परिवहन मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 31 का लोप किया जाएगा;
  - (iii) "सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 19 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-  
"19. 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक की परियोजनाओं को मानीटर करना।";

(48)

10

- (iv) "योग्यता आयोग" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 11 और नदारीय विभाग के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अतः स्थापित की जाएगी अर्थात्

12. भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण--

(क) भारत में निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्यात्मक सम्बन्धी नीति, योजनाएं और कार्यक्रम तथा उनसे सम्बन्धित सभी मामलों।

(ख) भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और उससे सम्बन्धित मामलों।

प्रतिभा देवीसिंह फटील

राष्ट्रपति

(फा.सं. 1/22/1/2010-मंत्री.)

MOST IMMEDIATE

No. K-13011/2/2009- DDIB  
Government of India  
Ministry of Urban Development  
[Delhi Division IB]

Nirman Bhawan, New Delhi.  
Dated : 22<sup>nd</sup> March, 2010

OFFICE MEMORANDUM

MC  
485  
23/3/10

PC-Secy  
Com(Pls.)

Separate Copies.

Subject:- Corrigendum to Gazette Notification No. S.O.1753(E) dated 14<sup>th</sup> July, 2009—regarding change of land use of land at Ghitorni.

23/3/10

A copy of the corrigendum to Notification dated 14.7.2009 referred to above, published in the Gazette of India Extraordinary under S.O.No.572(E) dated 10<sup>th</sup> March, 2010 is sent herewith for information and necessary action.

समाध्यक्ष कार्यालय  
जयपुर सं. 675-B  
दिनांक 22/3/2010

22/3/10

(U.Viswanadham)  
Under Secretary to Govt. of India  
Tel.No.23061681

141-G-Pls  
23/3/10

Copy to:

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi
2. Chairperson, NDMC, Palika Kendra, New Delhi
3. Commissioner (MCD), Town Hall, Delhi
4. Principal Secretary (UD), Govt. of National Capital Territory of Delhi, I.P.Estate, Delhi.
5. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Sadan, New Delhi.
6. L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.

23/3/10  
PS #ncus

23/3/10 (MC)

Copy to:- NIC, M/o UD to put the above corrigendum on the website of this Ministry Immediately.

23/3/10

(MC)

—12—

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 481]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 10, 2010/फाल्गुन 19, 1931

No. 481]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 10, 2010/PHALGUNA 19, 1931

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली खंड)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2010

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th March, 2010

का.आ. 572(अ).—शहरी विकास मंत्रालय के असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 1753(अ) दिनांक 14 जुलाई, 2009 (के-13011/2/2009-डी डी आई बी) के संदर्भ में ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. उक्त अधिसूचना के पैरा-5 के नीचे संशोधन के अन्तर्गत तालिका के कॉलम 2 के अन्तर्गत "क्षेत्रफल" को ठीक करके "96.98 हैक्टेयर (239.64 एकड़) पढ़ा जाए।"

3. उक्त सारणी के कॉलम 4 के अन्तर्गत मद—"(ii) सरकारी कार्यालयों 2792 हैक्टेयर" को ठीक करके "(ii) सरकारी कार्यालय 28.18 हैक्टेयर" पढ़ा जाए एवं "योग" को ठीक करके "योग: 96.98 हैक्टेयर (239.64 एकड़)" पढ़ा जाए।

[फा. सं. के-13011/2/2009-डी डी आई बी]

यू. विश्वनाथम, अवर सचिव

S.O. 572(E).—Reference is invited to the Ministry of Urban Development's Extraordinary Gazette Notification No. S.O. 1753(E) dated 14th July, 2009 (K-13011/2/2009-DDIB).

2. The "Area" under Column 2 of the Table under "Modification" below para-5 of the said notification may be corrected to read as "96.98 Ha (239.64 acres)."

3. Under Column 4 of the said Table—item "(ii) Government Offices 27.92 Ha." may be corrected to read as "(ii) Government Offices 28.18 Ha" and the "Total:" may be corrected to read as "Total : 96.98 Ha (239.64 acres)."

[No. K-13011/2/2009-DDIB]

U. VISWANADHAM, Under Secy.

-1-

(To be published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India)

Government of India  
Ministry of Urban Development

Nirman Bhawan, New Delhi,  
Dated the May 30, 2011

**Notification**

G. S. R. - In exercise of the powers conferred by sub-section(1), read with clause (g) of sub-section (3) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby nominates Shri Arun Goel, Joint Secretary (Delhi & Lands), Ministry of Urban Development, as Member of the Delhi Development Authority with immediate effect.



(N.T. Joseph)  
Under Secretary (DD IA)  
Tel: 23061478

SECRETARY'S OFFICE  
26/6/11  
3/1/11

(File No. K-11011/21/2004-DDIA)

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Ring Road, Mayapuri,  
New Delhi.

Copy forwarded for Information to :

1. The Secretary to Lt. Governor Delhi.
2. The Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi.
3. The Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan New Delhi.
4. The Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, IP Estate, New Delhi
5. The Engineer Member, DDA, Vikas Sadan, New Delhi.
6. The Finance Member, DDA, Vikas Sadan, New Delhi.
7. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi
9. Shri Arun Goel, Joint Secretary (D&L), M/o UD, Nirman Bhawan, New Delhi.



Under Secretary (DD IA)

21/6/11  
ADJUTANT  
17/6/2011  
MIA

MC  
1/80  
1/6/11

DD(MC)

3/1/11

(To be published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary)

Government of India  
Ministry of Urban Development  
(Delhi Division)  
\*\*\*\*\*

उपाध्यक्ष कार्यालय  
डायरी सं 1383-B...  
दिनांक 8/6/2011

Nirman Bhawan, New Delhi  
Dated the June 3, 2011

**NOTIFICATION**

STAMPED OFFICE  
27667  
9/6/11  
Date

S.O. - In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 5 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Raj Rewal, as Chairman (Part Time) and Smt. Sonali Bhagwati, Shri Eric P. Mall, Shri Satish Khanna and Joint Secretary (DL) in the Ministry of Urban Development, as Members (Part Time) in the Delhi Urban Art Commission (DUAC), for a period of three years from the date of assumption of the charge of the post, or until further orders, whichever is earlier. The Central Government also hereby nominates the representative of the Government of NCT of Delhi as permanent invitee to the meetings of the Commission.

*Signature*  
Comm (Res.)  
Comm (Plg.)  
(Secretary of Govt. of NCT of Delhi)

*Signature*

(N.T. Joseph)  
Under Secretary (DD IA)  
Tel: 23061478  
(No. A-11013/2/2011-DDIA)

To  
The Manager,  
Government of India Press, (along with Hindi version)  
Mayapuri, Rind Road,  
New Delhi.

DD (MC)

Copy forwarded to :-

*Signature*

ME  
19/6/11

1. Shri Raj Rewal, S-7, Triveni, DDA Commercial Complex, Sheikh Sarai, Phase-I, New Delhi-110017.
2. Smt. Sonali Bhagwati, S-296, Greater Kailash Part II, New Delhi-110048.
3. Shri Eric P. Mall, F-242, Sarita Vihar, New Delhi-110044.
4. Shri Satish Khanna, 58, Godawari Apartments, Alaknanda, New Delhi-110019.
5. Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Lodi Road, New Delhi.  
The Chairman and Members may be advised not to get associated in the examination, consideration and clearance of projects in which they have any personal interest.
6. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi.
7. Secretary to the Lt. Governor, Delhi, Raj Niwas, Delhi.
8. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA Colony, New Delhi.
9. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
10. Chairman, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
11. Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board, Delhi Cantt., Delhi.
12. Chief Town Planner, TCPO, I.P. Estate, New Delhi-2.
13. Information Officer, Ministry of Urban Development.
14. PS to UDM/PS to MoS(UD)/Sr.PPS to Secy.(UD)/PS to AS(UD) and PSs to all Joint Secretaries in the M/o U.D.
15. Director (DD), MoUD.

*Signature*

Under Secretary (DD IA)